भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DAINIK BHASKAR DELHI 19 MARCH 2026

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार, 28 को उद्घाटन के आसार

नोएडा एयरपोर्ट: मिनटों में सुरक्षा जांच, बैगेज स्कैनिंग 5 गुना तेज... 20 मिनट में बोर्डिंग संभव

कृष्ण मोहन तिवारी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से

शुरुआत के 45 दिन बाद 10 घरेलू रूट पर उड़ान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) के पार्किंग एरिया से फोरकोर्ट जाने की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो वाराणसी व हरिद्वार के घाटों की झलक मिलेगी। यहां पश्चिम यूपी की विशाल हवेलियों की तर्ज पर बने फोरकोर्ट में सैकड़ों वर्कर्स काम पूरा कर रहे हैं। एनआईए की टीमें मॉक ड्रिल कर रही हैं, ताकि एयरपोर्ट खुले तो कोई दिक्कत न आए। करीब 1334 हेक्टेयर में फैला यह एयरपोर्ट एरिया के हिसाब से देश का चौथा बड़ा एयरपोर्ट होगा। खूबी यह है कि एंट्री के बाद 20 मिनट से कम में से बोर्डिंग संभव है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा, पीएम नरेंद्र मोदी से शुभारंभ 28 मार्च को करने के लिए आग्रह किया गया है।

नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने हाल ही में कहा था, उद्घाटन के 45 दिन में ऑपरेशन शुरू होगा। शुरुआत 10 घरेलू रूट्स से होगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ तय हैं। वाराणसी, जयपुर, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद, श्रीनगर की भी उड़ान हो सकती हैं। शुरू में घरेलू उड़ानें होंगी और एयरपोर्ट दिन में ही ऑपरेशनल रहेगा। फिर रात की फ्लाइट शुरू होंगी। विदेशी उड़ानों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी-एयरोड्रोम सिक्योरिटी प्रोग्राम की मंजूरी बाकी है। शेष पेज 10 पर

भविष्य: 1 करोड़ यात्री पूरे होते ही दूसरा फेज

पहले फेज में एयरपोर्ट क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की है। एक करोड़ यात्री पहुंचते ही दूसरा फेज शुरू होगा। टी1 के ठीक सामने उसका दर्पण प्रतिबिंब टी2 बनेगा। बीच में फोरकोर्ट, घाट जैसी सीढ़ियां। क्षमता 3 करोड़, फिर 5 करोड़ और 7 करोड़ तक बढ़ेगी। 2050 तक सभी चार फेज पूरे होने हैं।

- अभी सिंगल रनवे है। हर घंटे 35-40 लैंडिंग और टेकऑफ संभव। रनवे 3,900 मीटर लंबा।
- 28 विमान पार्क हो सकेंगे। पार्किंग में रिफ्यूलिंग की सुविधा।
- **कनेक्टिविटी:** यह एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। दिल्ली-एनसीआर, आगरा, मथुरा-वृंदावन से सीधी कनेक्टिविटी। ईस्टर्न पेरिफेरल, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक और नए कॉरिडोर इसे उत्तर भारत का प्रमुख एविएशन हब बनाएंगे। मेट्रो-रैपिड रेल कनेक्टिविटी पर काम जारी।

एंट्री से बोर्डिंग तक पूरी तरह स्मार्ट... 48 चेक इन काउंटर तैयार, दिल्ली एयरपोर्ट से एक-तिहाई कम चलना होगा...

स्टेप 1: डिपार्चर के लिए छह गेट तैयार

फोरकोर्ट से डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए पहले फ्लोर पर जाना होगा। कुल छह गेट हैं। सभी डिजी यात्रा बायोमैट्रिक सिस्टम से लैस हैं, यानी चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। डिजीयात्रा न होने पर मैन्युअल चेक-इन भी रहेगा।

स्टेप 2: 30 सेकंड में खुद जमा करें बैग

सेल्फ बैग ड्रॉप सिस्टम है। 30 सेकंड में बैग जमा कर सकेंगे। एक मशीन प्रति घंटे 80 से 100 यात्रियों को हैंडल कर सकती है, जो मैन्युअल काउंटर से 4 गुना तेज है। 48 चेक इन काउंटर, 9 सिक्योरिटी लेन्स, 19 इमिग्रेशन काउंटर।

स्टेप 3: हाई स्पीड सिस्टम से बैगेज जांच

सीमेंस वैरियो-ट्रे सिस्टम पर हर मिनट 60 ट्रे गुजरेंगी। स्पीड 10 मीटर/सेकंड, जो दिल्ली एयरपोर्ट के आईसीएस के 2.1 मी/सेकंड से 5 गुना तेज। ये सिस्टम दुबई, बीजिंग, पेरिस जैसे एयरपोर्ट पर है। 13 सुरक्षा गेट, 6 एक्सरे जोन हैं।

स्टेप 4: 60 मीटर का कॉरिडोर...बोर्डिंग

सुरक्षा जांच के बाद करीब 60 मीटर का कॉरिडोर पार करना होगा। एंट्री से बोर्डिंग गेट तक 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। अगर, दिल्ली से तुलना करें तो, टी3 में एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक करीब 15-30 मिनट की वॉकिंग है।

सभी सीट पर चार्जिंग... 70% सामान्य चेयर हैं, सभी में चार्जिंग पॉइंट हैं। वाई-फाई के साथ 20% वर्क स्टेशन हैं। 10% स्लीपिंग-रिक्लाइनर चेयर हैं। प्रेयर रूम और बच्चों के लिए अलग प्ले एरिया।

फूड, लाउंज में मथुरा के पेड़े और कचौरी के साथ ग्लोबल अनुभव...होटल भी बन रहा

यह फूड-बेवरेजेस में लोकल से ग्लोबल स्वाद मिलेगा। बेड़मी पूरी-आलू की सब्जी, मथुरा के पेड़े, कचौड़ी, जलेबी जैसे स्थानीय व्यंजन के साथ केएफसी, सबवे, डोमिनोज जैसे विकल्प मिलेंगे। एयरपोर्ट परिसर में ही 220 कमरों वाला लग्जरी 'रोजिएट' होटल है, जिसमें डिजिटल चेक-इन और प्रीमियम सुविधाएं होंगी।

नोएडा एयरपोर्ट: मिनटों में सुरक्षा...

जेवर एयरपोर्ट: देश का पहला नेट-जीरो एनर्जी टर्मिनल होगा

10 मेगावाट सोलर पार्क से ग्रीन एनर्जी, सभी वाहन भी इलेक्ट्रिक। हवेली कॉन्सेप्ट से दिन में प्राकृतिक रोशनी, आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत कम पड़ेगी।

स्मार्ट फसाड: पश्चिमी दीवार 70% गर्मी रोकती है, उत्तरी दीवार से रनवे व्यू। साल के 8 महीने प्राकृतिक हवा, एसी पर निर्भरता कम। गेट एरिया में ज्यादा कूलिंग, बाकी जगह कम इससे ऊर्जा की भारी बचत होगी।

कम चलना... तेज प्रोसेस यही एयरपोर्ट की पहचान

एयरपोर्ट की सबसे बड़ी पहचान कम चलना, छोटी कतारें और तेज प्रोसेस होगी। इंडिगो लॉन्च पार्टनर है, अकासा, एयर इंडिया एक्स. से करार हो चुका है। दुबई-हीथ्रो जैसा इंटरनेशनल ट्रांजिट हब बनने की क्षमता है। -क्रिस्टोफ श्नेलमान, सीईओ, एयरपोर्ट

कम दृश्यता में भी जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें सुनिश्चित: पढ़ें बिजनेस पेज पर

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DESHBANDHU DELHI 19 MARCH 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बताया गेमचेंजर, कहा

उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी में होगी ऐतिहासिक बढ़ोतरी

ग्रेटर नोएडा, 18 मार्च (देशबन्धु)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'नव निर्माण के 9 वर्ष' कार्यक्रम के दौरान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर बताया। उन्होंने कहा कि जेवर में तैयार हो चुका यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसके लोकार्पण के लिए 28 मार्च की तिथि प्रस्तावित करते हुए प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट शुरू होते ही उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। इससे न केवल निवेश को गति मिलेगी, बल्कि प्रदेश सरकार को लगभग एक लाख करोड़ रुपये तक की आय होने का अनुमान है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि एयरपोर्ट के साथ विकसित हो रहा पूरा क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र, देश का नया आर्थिक हब बन रहा है, जहां तेजी से उद्योग, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। सीएम के अनुसार, बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत नीतियां और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल ने यूपी को निवेश का प्रमुख केंद्र बना दिया है, जिसमें जेवर एयरपोर्ट की भूमिका निर्णायक साबित होगी।

इसी महीने पूरा हो रहा गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य

सीएम योगी ने 2017 के पहले राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की दुर्दशा का जिक्र किया, फिर अपनी सरकार के कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि देश का 55 फीसदी एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। गंगा एक्सप्रेसवे इसी महीने पूरा हो रहा है। इसके पश्चात यूपी का शेयर 60 फीसदी हो जाएगा। यूपी ने इंटरस्टेट, इंटरनेशनल, फोरलेन कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। मैत्रीद्वार बनाए गए

■ **नोएडा एयरपोर्ट के लोकार्पण की उलटी गिनती शुरू, 28 मार्च के लिए पीएम को आमंत्रण**

हैं। सीएम ने यूपी में आए परिवर्तनों को भी इंगित किया और कहा कि हर जिला मुख्यालय फोरलेन, ब्लॉक-तहसील मुख्यालय टू लेन-फोर लेन कनेक्टिविटी से जुड़ा है।

सिंगापुर, जापान व जर्मनी से बड़े पैमाने पर आने वाले हैं निवेशक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी हम लोग जापान और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। मेरे साथ वित्त व औद्योगिक विकास मंत्री भी थे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व आईटी मंत्री जर्मनी की यात्रा पर गए थे। उन देशों में सभी वरिष्ठ मंत्री व इंडस्ट्री लीडर्स कहते थे कि हम यूपी में इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि वहां जीरो टॉलरेंस व जीरो करप्शन की नीति है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी निवेश का बेहतरीन

देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा आर्थिक ग्रोथ का इंजन, यूपी को मिलेगा 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व : योगी आदित्यनाथ

डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। सिंगापुर, जापान और जर्मनी से बड़े निवेशक यूपी आने वाले हैं। अभी से पत्र आने प्रारंभ हो गए हैं। सरकार ने इस पर कार्य भी शुरू कर दिया है। जिस प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आता था, वहां अब तक 15 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हैं। छह लाख करोड़ रुपए का निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार है। हर जिले में निवेश हो रहा है। हमारे पास व्यापक लैंडबैंक है। 34 सेक्टोरल पॉलिसीज, निवेश मित्र व निवेश सारथी जैसी उद्यम समर्थित व्यवस्थाएं है। प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है।

'सुरक्षा, पॉलिसी, लैंडबैंक व सरकार की नीयत नहीं होने से 2017 के पहले नहीं आते थे निवेशक'

सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले निवेशक नहीं आता था, क्योंकि यहां सुरक्षा, पॉलिसी, लैंडबैंक और सरकार की नीयत भी नहीं थी। 1947 से 2017 तक बमुश्किल 14 हजार से कम उद्योग थे, आज राज्य में अब तक 31 हजार बड़े उद्योग लग चुके हैं। यूपी में 96 लाख एमएसएमई यूनिट कार्यरत हैं, जिसमें 3.11 करोड़ लोग कार्यरत हैं। 31 हजार से अधिक उद्योगों में 65 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। निवेश तब आता है, जब सरकार की नीयत अच्छी होती है।

नोएडा जाने के अपशकुन को हमने उखाड़ फेंका

सीएम ने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हमारी आस्था को अंधविश्वास बोलते थे, वे नोएडा नहीं जाते थे। उन्हें लगता था नोएडा जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। मुझे दायित्व मिला तो मैंने कहा कि नोएडा जाएंगे। लोगों ने कहा कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाते हैं, उनकी कुर्सी चली जाती है। मैंने कहा कि कुर्सी आज चली जाए, लेकिन प्रदेश का भला होगा तो नोएडा जाएंगे और विकास पर लगे बैरियर को हटाएंगे।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा आज देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। यदि हम लोग नोएडा नहीं जाते तो देश में 55 फीसदी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60 फीसदी निर्माण यूपी में नहीं हो पाता। नोएडा जाना यूपी के लिए अपशकुन बना दिया गया था। तब के मुख्यमंत्री उसका माध्यम बने थे। हमने कहा कि अपशकुन को उखाड़ फेकेंगे और इसे विकास में बाधा नहीं बनने देंगे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DECCAN HERALD BANGALORE 18 MARCH 2026

Airport push must pass viability test

The renewed push to build an airport in Ballari has again brought to the fore a familiar dilemma in infrastructure planning: should such projects be guided by economic viability or by political optics? The discussion assumes urgency as the Karnataka government prepares to hold a meeting between Chief Minister Siddaramaiah and legislators from Ballari, Vijayanagara, and Koppal to explore the possibility of establishing a common airport for the region. The proposal deserves careful consideration, but it must not be reduced to a prestige contest among districts. Airports are among the most capital-intensive public infrastructure projects. Once built, they demand continuous expenditure on maintenance, security, and navigation systems. If passenger demand is weak, such facilities quickly turn into white elephants.

Unfortunately, the experience of India's regional aviation programme offers ample evidence of this risk. The UDAN Scheme was launched to democratise air travel by connecting smaller cities. While it brought nearly a hundred airports onto the aviation map, many were reduced to silent terminals once the initial subsidy period ended. Under the scheme, airlines receive viability gap funding for only three years. When this support expires, carriers operating on thin margins often withdraw from routes that cannot sustain commercial operations. Across the country, several airports built with great fanfare now see little or no traffic. The pattern is visible even in Karnataka. Airports in Mysuru and Shivamogga handle just a handful of services, while Kalaburagi has struggled to maintain consistent connectivity. These examples highlight that airports cannot thrive merely because they are built; they survive only when passenger demand justifies their existence. This is why the suggestion of creating a single, strategically located airport to serve Ballari, Vijayanagara, and Koppal merits attention. A consolidated regional hub, accessible to neighbouring districts and even parts of Andhra Pradesh, would concentrate passenger traffic and improve the chances of commercial sustainability. Building airports for each district may satisfy local pride, but it risks repeating the costly mistakes seen elsewhere.

Passenger demand and economic sustainability should shape the Ballari airport proposal

The Karnataka government's proposal to extend the subsidy framework and develop its own civil aviation policy is welcome. However, policy reform alone will not suffice unless infrastructure decisions are grounded firmly in rigorous feasibility studies. Many airports have been built in places where road and rail connectivity are excellent, making air travel an unnecessary and more expensive option. Infrastructure must serve people, not political symbolism. Airports will truly take flight only when they are economic gateways that sustain connectivity and growth. They must be built on viability, not vanity.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DAINIK JAGRAN DELHI 19 MARCH 2026

28 मार्च को नोएडा एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ: देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंतजार खत्म होने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपनी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में तैयार है। हमने 28 मार्च को इसके लोकार्पण के लिए पीएम से अनुरोध किया है। नोएडा एयरपोर्ट से प्रदेश सरकार को एक लाख करोड़ रुपये की आय होगी।

करीब 1300 हेक्टेयर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसे पीपीपी माडल के तहत विकसित किया गया है। इसका पहला चरण सितंबर 2024 में ही पूरा किया जाना था, लेकिन तकनीकी और निर्माण कारणों से इसमें देरी हुई।

समय के अभाव में अप्रैल तक टल सकता है शुभारंभ

जागरण, जेवर: नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी जोर-शोर से चल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से लोकार्पण की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। संभावित 26 से 28 मार्च के कार्यक्रम के लिए अब समय बहुत कम बचा है। भाजपा लोकार्पण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री की भव्य रैली कराना चाहती है जिसके लिए कम से कम 15 से 20 दिनों के समय की आवश्यकता है। ऐसे में माना जा रहा कि एयरपोर्ट के लोकार्पण का कार्यक्रम अप्रैल में पांच राज्यों में मतदान से पूर्व कराया जाए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

RS DAINIK JAGRAN DELHI 19 MARCH 2026

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 28 मार्च को उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मार्च को इसका उद्घाटन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपनी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में तैयार है। हमने 28 मार्च को इसके लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। जेवर एयरपोर्ट से अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी होगी और प्रदेश सरकार को एक लाख करोड़ रुपये की आय होगी।' पहले चरण में करीब 1300 हेक्टेयर में बना एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसे पीपीपी माडल के तहत विकसित किया गया है। इसका पहला चरण सितंबर 2024 में ही पूरा किया जाना था, लेकिन तकनीकी और निर्माण कारणों से इसमें देरी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे नेटवर्क यूपी के पास है। गंगा एक्सप्रेसवे इसी महीने पूरा हो रहा है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DAINIK NAVJYOTI JAIPUR 17 MARCH 2026

जयपुर एयरपोर्ट पर आज से नोटम लागू रोज 4 घंटे फ्लाइट संचालन बंद

नवज्योति,जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर 17 से 23 मार्च तक नोटम लागू रहेगा, जिसके चलते रोजाना चार घंटे तक फ्लाइट संचालन प्रभावित रहेगा। इस अवधि में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक एयरपोर्ट से किसी भी फ्लाइट का संचालन नहीं किया जाएगा। नोटम के कारण कुल 6 फ्लाइट्स को रिशेड्यूल किया गया है, जबकि 2 फ्लाइट्स एक सप्ताह के लिए रद्द रहेंगी और एक फ्लाइट की फ्रिक्वेंसी घटाई गई है। नोटम के चलते एयर इंडिया की दो फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली जाने वाली फ्लाइट अब दोपहर 1.30 बजे के बजाय 12.55 बजे रवाना होगी, जबकि मुंबई जाने वाली फ्लाइट दोपहर 1.35 बजे के बजाय 12.45 बजे रवाना होगी। इसी तरह इंडिगो की सूरत जाने वाली फ्लाइट जो पहले दोपहर 2.20 बजे उड़ान भरती थी वह अब 12.50 बजे जाएगी। स्पाइसजेट की मुंबई जाने वाली फ्लाइट का समय भी बदला गया है। यह फ्लाइट पहले दोपहर 3.05 बजे रवाना होती थी, लेकिन नोटम अवधि के दौरान अब रात 9.50 बजे उड़ान भरेगी। वहीं शाम 5.05 बजे जाने वाली एयर इंडिया की दिल्ली फ्लाइट अब शाम 5.40 बजे जाएगी, जबकि शाम 5.10 बजे इंडिगो की नवी मुंबई फ्लाइट अब शाम 5.50 बजे रवाना होगी। नोटम के कारण दो फ्लाइट्स को अस्थायी रूप से रद्द भी किया गया है। इंडिगो की दोपहर 1.25 बजे जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट और दोपहर 1.55 बजे दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 17 से 23 मार्च तक रद्द रहेंगी। ये दोनों फ्लाइट्स 24 मार्च से फिर से नियमित रूप से संचालित होंगी। इसके अलावा इंडिगो की चंडीगढ़ फ्लाइट की फ्रिक्वेंसी भी घटा दी गई है। सामान्य दिनों में यह फ्लाइट सप्ताह में पांच दिन संचालित होती है, लेकिन नोटम अवधि में वह केवल एक दिन चलेगी। 22 मार्च को यह फ्लाइट दोपहर 1.45 बजे के बजाय 12.50 बजे रवाना होगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

THE FINANCIAL EXPRESS DELHI 19 MARCH 2026

PM MAY OPEN NOIDA AIRPORT ON MARCH 28

UTTAR PRADESH CHIEF Minister Yogi Adityanath on Wednesday said a request had been sent to Prime Minister Narendra Modi to inaugurate the Noida International Airport at Jewar on March 28. He was speaking at an event in Lucknow.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

HINDUSTAN DELHI 19 MARCH 2026

नोएडा एयरपोर्ट का शुभारंभ 28 को होने की संभावना

प्रोजेक्ट अपडेट 1

लखनऊ/ग्रेटर नोएडा, हिटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करने का अनुरोध किया है। शुभारंभ के बाद अर्थव्यवस्था में और तेजी आएगी। प्रदेश सरकार को एक लाख करोड़ रुपये की आय होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसी महीने गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा हो जाएगा। जापान, सिंगापुर और जर्मनी के मंत्री और निवेशक कहते हैं कि यूपी में जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति है इसीलिए वे निवेश करने आ रहे हैं। वहीं, जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल के आसपास की सड़कों समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है।

> नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। मौके पर पंडाल लगाने और कुर्सियां बिछाने का कार्य जारी है। हालांकि, उद्घाटन की तिथि को लेकर शासन से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए। -**आरके सिंह**, सीईओ, यीडा

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को मुख्यमंत्री ने लखनऊ में ऐलान किया कि नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को न्योता भेजा गया है। हालांकि, अभी पीएमओ से तिथि घोषित नहीं की गई है। जिलास्तर पर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिए गए हैं। दूसरी ओर, जिला प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन भी तैयारियों में जुटा हुआ है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE HINDUSTAN TIMES DELHI 19 MARCH 2026

Invited PM to inaugurate Noida int'l airport on March 28: UP CM

Vinod Rajput
vinod.rajput@htlive.com

GREATER NOIDA: Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath on Wednesday said he has invited Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Noida International Airport on March 28 as it is ready to start the domestic and cargo operations.

"The international airport at Jewar is ready and will be the largest in the country. We have invited the Prime Minister to inaugurate it on March 28. Jewar airport will boost economic growth and generate ₹1 lakh crore revenue for the state government," said Yogi in an address delivered during a release of a book "Nav Nirman ke 9 Varsh" in Lucknow.

Official said that the Prime Minister's Office is yet to give confirmation for the March 28 inauguration event.

Yogi said the Jewar located Noida International Airport will be the fifth international airport in UP.

He said the UP has now transformed into an infrastructure-focused state with the largest railway network in the country, adding that metro services are operational in seven cities – Lucknow, Kanpur, Agra, Noida, Greater Noida, Ghaziabad and Meerut, and there are 16 airports operational in the state.

Meanwhile, on Tuesday, Gautam Budh Nagar district magistrate Medha Roopam, convened a meeting of the Airport Emergency Planning Committee (AEPC) and Airport Environment Management Committee (AEMC) to review the airport's emergency preparedness, structured coordination, and modern infrastructure, said officials.

During the meeting, the DM emphasised on the need for a robust coordination among all partner agencies to ensure timely, effective, and integrated response in any emergency situation. She ordered that drones will not be allowed in the no-flying zone and laser lights will be prohibited within 18 kilometres of the airport perimeter.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

MILLENNIUM POST DELHI 19 MARCH 2026

Noida Airport likely to be inaugurated on March 28

BISWAJEET BANERJEE

LUCKNOW: The Yogi Adityanath government has proposed March 28 for the inauguration of the Noida International Airport at Jewar, with an invitation extended to Prime Minister Narendra Modi to preside over the ceremony.

Talking about air connectivity, he mentioned that 16 airports are operational in the state, including four international airports. "Fifth international airport at Jewar is ready and will be the largest in the country. We have invited Prime Minister to inaugurate it on March 28," Chief Minister Yogi Adityanath said.

Speaking at an event marking nine years of his government in Uttar Pradesh, Chief Minister Adityanath said the airport would be a major economic driver for the state. He said the project is expected to contribute around Rs 1 lakh crore to the state's economy.

> **"The greenfield airport, located on the outskirts of Noida, is being developed under a public private partnership model"**

The development comes after the Directorate General of Civil Aviation granted the aerodrome licence for the Jewar airport on March 6, clearing the final regulatory requirement for the commencement of flight operations. The licence permits both domestic passenger services and cargo operations.

Officials said the airport infrastructure is largely ready, with final operational arrangements and staff deployment expected to be completed shortly. Shailendra Bhatia, nodal officer of Noida International Airport Limited, had earlier indicated that the project is in its final stages of readiness.

The greenfield airport, located on the outskirts of Noida, is being developed under a public private partnership model. Once fully operational, it is expected to rank among the largest airports in the country.

In its first phase, the project covers around 1,300 hectares and includes a runway and a terminal capable of handling about 1.2 crore passengers annually, according to officials.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

NAVBHARAT TIMES DELHI 19 MARCH 2026

सिर्फ 10 दिन में शुरू होगा नोएडा एयरपोर्ट

■ NBT रिपोर्ट, ग्रेटर नोएडा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 28 मार्च को नोएडा इंटरनैशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री को न्योता देने के बयान के साथ ही यहां तैयारियों ने गति पकड़ ली है। शुभारंभ समारोह और जनसभा के लिए टेंट लगने का काम शुरू हो गया है। अफसर भी अलर्ट मोड पर हैं। तैयारियों को लेकर बैठकें भी कर चुके हैं। हालांकि अभी पीएमओ से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।

एयरपोर्ट के अंदर टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है। कुछ टेंट लग चुके तो कुछ सामान भी पहुंचा है। इससे पहले भी एयरपोर्ट के शुभारंभ की चर्चा हुई थी, लेकिन कार्यक्रम नहीं हुआ था। तब भी टेंट लगा था, लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पाया था। अब प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। नोएडा इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ आरके सिंह पिछले एक हफ्ते में दो बार नोएडा एयरपोर्ट का दौरा कर चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी सतर्क हैं और बैठकें कर रहे हैं। समारोह और रैली की तैयारियों को लेकर मंगलवार को नोएडा एयरपोर्ट परिसर में जिलाधिकारी मेधा रूपम, यमुना अथॉरिटी के सीईओ राकेश कुमार सिंह, एडिशनल कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा ने उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने भी तैयारियों की समीक्षा की।

विकास प्राधिकरण
एडा, गौतमबुद्ध नगर
.com

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE PIONEER DELHI 19 MARCH 2026

PM invited to open Jewar airport

PIONEER NEWS SERVICE
Lucknow

Chief Minister Yogi Adityanath on Wednesday said a request has been sent to Prime Minister Narendra Modi to inaugurate the Noida International Airport at Jewar on March 28.

Addressing an event, CM Adityanath said Uttar Pradesh has significantly expanded its air connectivity in recent years.

"For connectivity in the country, especially air connectivity, Uttar Pradesh today has 16 domestic airports and four international airports. The fifth international airport in the country is coming up at Jewar. We have sent a request to Prime Minister for its inauguration on March 28 and have invited him," he said.

He added that the airport is expected to give a major boost to the State's economy.

"Imagine the scale of growth once the Jewar airport becomes operational. It is expected to generate revenue of around Rs 1 lakh crore for the Uttar Pradesh Government," the CM said.

CONTINUED ON >> P4

PM invited to open Jewar airport

The remarks come days after Noida International Airport CEO Christoph Schnellmann met Adityanath in Lucknow and presented the aerodrome licence issued by the Centre for the airport. The Noida International Airport, being developed at Jewar in Gautam Buddha Nagar district under a public-private partnership model, is a major greenfield project aimed at boosting connectivity between the National Capital Region, western Uttar Pradesh and key domestic and international destinations.

In its first phase, the airport will have one runway and a passenger terminal with an annual handling capacity of around 12 million passengers.

The terminal, spread over about 1.38 lakh square metres, will include 48 check-in counters, nine security screening lanes and nine immigration counters, along with domestic and international lounges.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

SWATANTRA BHARAT LUCKNOW 18 MARCH 2026

एयरपोर्ट पर 8.55 करोड़ की ड्रग्स बरामद

स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ। एयरपोर्ट पर मस्कट से आए एक यात्री के पास से 8.55 करोड़ का गांजा (हाइड्रोपोनिक वीड) पकड़ा गया। आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को ओमान एयर की उड़ान (डब्ल्यूवाई 265) से लखनऊ पहुंचे एक संदिग्ध यात्री के सामान की जांच के दौरान गांजा मिला। खुफिया इनपुट के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें प्रतिबंधित पदार्थ छिपाकर रखा गया था। जांच के दौरान यात्री के काले-भूरे रंग के बैकपैक से 17 वैक्यूम पॉलीबैग मिले। इन पैकेटों को कैमलिन कार्बन पेपर में लपेटकर छिपाया गया था। पैकेटों में हरे रंग का पदार्थ पाया गया, जिसके हाइड्रोपोनिक वीड होने की आशंका

है। बरामद पदार्थ का कुल वजन 8.552 किलोग्राम है। सीमा शुल्क विभाग ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस गांजे की अनुमानित कीमत 8,55,20,000 रुपए आंकी गई। बरामदगी के बाद मादक पदार्थ को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के तहत जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने आरोपी यात्री को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले में आगे की जांच जारी है और तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE ASIAN AGE DELHI 19 MARCH 2026

Airlines told: Keep 60% of all seats free

■ *DGCA relief for passengers* ■ *Seat those on same PNR together*

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, MARCH 18

THE AVIATION regulator's moves come against the backdrop of rising concerns that airlines are levying high charges for various services, including for choosing seats

In a major relief to passengers, the Directorate-General of Civil Aviation (DGCA) has ordered all domestic airlines to keep at least 60 per cent of seats on all flights free of charge to ensure fair access. It has also directed that passengers travelling on the same PNR should be seated together, preferably in adjacent seats.

The aviation regulator's moves come against the backdrop of rising concerns that airlines are levying high charges for various services, including for choosing seats. At present, 20 per cent of seats can be booked free of charge, while the rest is paid. The rates of seats are as per location, with the front row costing the maximum, followed by window and aisle seats. Seats in the centre and in the back rows near toilets cost less.

In a post on X on Wednesday, Union civil aviation minister K. Rammohan Naidu said important directions have been issued to further strengthen passenger facilitation measures. "Sixty per cent seats free of charge, assured seating together for families, and clear, transparent norms for carriage of sports equipment, musical instruments and pets," he said. According to him, there will be stronger enforcement and visibility of passenger rights, including during delays and cancellations.

As per DGCA orders, carriage of sports equipment and musical instruments to be facilitated in a transparent and passenger-friendly manner,

■ Turn to Page 4

Airlines told: Keep 60% of all seats free

■ Continued from Page 1

subject to applicable safety and operational regulations. Besides, airlines shall also bring out clear, transparent policies for carriage of pets.

Strict adherence to passenger rights framework, particularly in cases of delays, cancellations and denied boarding; prominent display of passenger rights across airline websites, mobile applications, booking platforms, and airport counters; and, clear communication of passenger entitlements in regional languages to ensure wider accessibility and awareness are other provisions that the airlines have been told to follow to further strengthen passenger convenience, transparency and uniformity of practices across airlines.

"The ministry of civil aviation remains committed to enhancing passenger experience, ensuring transparency, reducing grievances and upholding the highest standards of safety across the aviation ecosystem," the ministry said in a statement.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS LINE DELHI 19 MARCH 2026

Govt mandates 60% seats on flights to be free of selection fee

PROFIT STRAIN. Airlines uneasy on rising costs; ancillary revenues account for 10-15% of income

Rohit Vaid
New Delhi

In a passenger-centric move, the Centre has directed airlines to ensure that a minimum of 60 per cent of seats on flights are made available without any additional charge (seat selection fee), while also requiring carriers to seat passengers travelling on the same PNR together, preferably in adjacent seats.

As part of a broader push to improve transparency and standardisation, the Ministry of Civil Aviation, through the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), mandated airlines to clearly articulate policies on carriage of sports equipment, musical instruments and pets. Besides, the directions mandate airlines to prominently display passenger rights across platforms and ensure communication of entitlements in regional languages.

COST LAYERS. It is a significant move as airlines price travel components separately under unbundled services framework

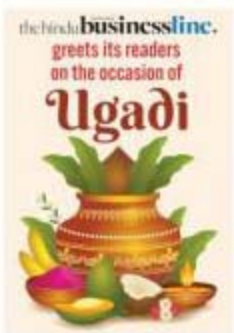

BUNDLED FRAMEWORK

The move assumes significance given the current unbundled services framework, in which airlines price various components of travel separately.

At present, most seat selections are chargeable, with passengers often paying extra for preferred seats or to ensure adjacent seating even when travelling on a single booking.

Ancillary revenues, including seat selection, baggage and onboard services like food and beverages, account for 10-15 per cent of airline revenues, with seat selection contributing a relatively smaller share within this segment.

RISING COST OF OPS

There is unease in the industry over the new norms, especially given the high cost of operations.

"Given the crude oil price situation, it is very difficult for airlines to survive if the government continues to enforce policies that are financially unviable for the sector," a senior executive of a leading low-cost carrier told *businessline*.

A senior executive of another airline said that the impact on fares may be limited as seat selection charges themselves typically start at around ₹200 and form a small portion of overall ancillary revenues.

Globally, such practices are uncommon, with most aviation markets allowing airlines the flexibility to price services under deregulated frameworks.

According to Mark Martin, Founder and CEO of Martin Consulting, "Selection of seats is considered a value-plus offering and preference. Although the 60 per cent limit will continue to allow airlines to sell window and aisle seats as a 'value-plus add-on', the bigger impact I see is with the Premium Economy product, as the middle seat in Premium Economy will need to be classified as a nil-value seat."

According to Kinjal Shah, Senior Vice-President and Co-Group Head, Corporate Sector Ratings, ICRA, the DGCA directive will not have any material impact on the revenues of the airlines.

"Ancillary revenues have accounted for less than 10 per cent of the revenues of India's airlines over the last few years. Ancillary revenues comprise seat selection charges, extra baggage charges and food sales, among others," she said.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS LINE DELHI 19 MARCH 2026

Pilot body demands rollback of flight duty relaxations to Air India, flags fatigue risks

Press Trust of India
Mumbai

Pilots' group ALPA India on Wednesday urged the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) to roll back the latest relaxations granted to Air India for two-pilot long-haul flights amid the West Asia conflict, saying pilots will be exposed to an "unacceptable level of fatigue risk".

SOARING TROUBLES. The temporary relaxations in FDTL norms are applicable till April 30

KEY CONCERNS

In a letter to the DGCA, the association raised concerns about the relaxation of flight duty time limitations (FDTL) norms for Boeing 787 operations in the wake of the West Asia conflict.

Last week, the DGCA provided temporary relaxations — extending the flight time by 1.30 hours to 11.30 hours and the flight duty period by 1.45 hours to 11.45 hours — in flight duty norms for Air India's long-haul flights as the airline is taking longer routes due to the airspace curbs amid the West Asia conflict, sources had said. These temporary relaxations in FDTL norms are applicable till April 30.

PRIOR CONSULTATION

While acknowledging that the relaxations were necessitated by the current situation, ALPA India flagged that there was lack of prior consultation with respect to the non-reclining pilot seats in Boeing 787 aircraft.

"The lack of prior consultation, particularly for Boeing 787 operations (non-reclining pilot seat), has understandably caused understandable concern among crews already stretched thin," the association's President Captain Sam Thomas said in the letter.

LONGER ROUTES

The DGCA has provided temporary relaxations in flight duty norms for Air India's long-haul flights as the airline is taking longer routes due to the curbs caused by the West Asia conflict.

The pilot's group sought war-risk insurance coverage for the crew, staff and passengers as a kind of explicit reassurance that they are comprehensively covered by additional insurance overriding the standard "war risk exclusion" clauses in legacy policies. "Such confirmation would alleviate deep-seated anxieties and affirm the value placed on their trust. We urge the DGCA to kindly compel airlines to confirm this by means of a special circular for the benefit of the crew and for the solace of their families," it added.

On Tuesday, the group asked members to ensure that airlines carry out "appropriate operational risk assessments" before planning flights in or near conflict-affected areas.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS LINE DELHI 19 MARCH 2026

Gulf Air adds flights to Chennai for stranded flyers

Aneesh Phadnis
Mumbai

Passengers stranded in Bahrain and Kuwait can now travel to India via Saudi Arabia as Gulf Air and Jazeera Airways have introduced special flights.

While Gulf Air will operate flights from Dammam to Chennai from March 21-28, Jazeera Airways of Kuwait will operate flights to six cities in India from Qaisumah airport in Saudi Arabia. Jazeera Airways has already opened bookings for its first two flights to Kochi on March 20 and 21.

LIMITED SERVICES

Airports in Bahrain and Kuwait have been closed since start of conflict on February 28. With no direct connectivity available the airlines have started limited services from airports in Saudi Arabia. Indian Embassies in Bahrain and Kuwait co-ordinated with authorities and resident associations for these services.

Chennai international airport

Gulf Air has been operating a flights from Dammam to Mumbai, Bangkok and London. On Tuesday the airline added Cairo, Casablanca and Chennai to its temporary network. Gulf Air said transport between Bahrain and Dammam will be arranged by the airline for passengers holding confirmed tickets. The airline said it will also assist with Saudi transit visas for all such passengers.

Passengers will travel overland from Kuwait to Qaisumah. From Qaisumah, they will board outbound flights to their respective destinations. Incoming flights will also follow the same route, the airline said.

IndiGo said it is resuming flights to Dubai following the latest update from its civil aviation authority. The airline will operate one flight between Mumbai and Dubai on Thursday.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS STANDARD DELHI 19 MARCH 2026

उड़ानों में 60 फीसदी सीट पर अतिरिक्त शुल्क नहीं

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 18 मार्च

नागर विमानन मंत्रालय ने आज विमानन कंपनियों से कहा कि वे हर उड़ान में कम से कम 60 फीसदी सीटों को अतिरिक्त शुल्क से अलग रखे और यह सुनिश्चित करें कि एक ही पीएनआर वाले यात्रियों को आसपास ही बिठाया जाए।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक अधिकारी ने चिंता जताई थी कि विमानन कंपनियां और ट्रैवल एजेंट अपनी वेबसाइट पर 'डार्क पैटर्न' वाली तरकीबें अपना रहे हैं। वे यात्रियों को टिकट बुक करते समय या वेब चेक-इन के दौरान मनमाफिक सीट चुनने के लिए अतिरिक्त शुल्क देने के लिए उकसाते हैं। मगर वास्तव में अतिरिक्त शुल्क से मुक्त सीटों की संख्या काफी कम होती है। कई मामलों में तो अतिरिक्त शुल्क न देने पर एक ही पीएनआर वाले यात्रियों को अलग-अलग सीटों पर बिठाया जाता है जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। अब सरकार ने हर उड़ान में 60 फीसदी सीटों को अतिरिक्त शुल्क के दायरे से अलग रखने का नियम बनाया है। मगर इससे विमानन कंपनियों की अतिरिक्त आय और विशेष रूप से पसंदीदा सीट चुने जाने से होने वाली कमाई पर असर पड़ने की आशंका है। पसंदीदा सीट चुनने पर लिया जाने वाला शुल्क विमानन कंपनियों की अतिरिक्त आय का एक बड़ा हिस्सा होता है। विमानन कंपनियां मुनाफा बढ़ाने के लिए ऐसी सेवाओं पर अधिक निर्भर होती जा रही हैं। यह रुझान इंडिगो के वित्तीय नतीजों में साफ तौर पर दिखता है। वित्त वर्ष 2026 की दिसंबर तिमाही में उसकी अन्य स्रोतों से आय एक साल पहले की समान तिमाही के मुकाबले 13.6 फीसदी बढ़कर 2,446.2 करोड़ रुपये हो गई। यह यात्रियों के टिकट से होने वाली कमाई में 6.2 फीसदी की बढ़ोतरी के मुकाबले काफी अधिक थी। **(शेष पृष्ठ 2 पर)**

बेहतर यात्रा अनुभव

- सरकार ने एक ही पीएनआर वाले यात्रियों को साथ बिठाने का बनाया नियम
- पारदर्शिता और यात्रियों का अनुभव बेहतर करने पर मंत्रालय की नजर
- यात्रियों के अधिकारों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर भी जोर

उड़ानों में 60% सीट पर अतिरिक्त शुल्क नहीं

पृष्ठ 1 का शेष

टिकट बिक्री से प्राप्त आय एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय में अंतर उद्योग की एक बड़ी रणनीति को दर्शाता है जहां एक ओर प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए मूल किराये में अक्सर छूट दी जाती है जबकि सीट चुनने जैसी सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क लिए जाते हैं। इससे विमानन कंपनी को अपना मार्जिन बचाने में मदद मिलती है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। देश के हवाई अड्डों पर रोजाना 5,00,000 से अधिक यात्रियों की आवाजाही होती है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि सभी विमानन कंपनियों में यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और एक जैसे नियम होने चाहिए।

मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनियों को सुरक्षा एवं संचालन संबंधी नियमों के दायरे में रहते हुए खेल के सामान, संगीत उपकरण और पालतू जानवरों को ले जाने के लिए पारदर्शी एवं यात्रियों के अनुकूल नीतियां अपनानी चाहिए।

मंत्रालय ने यात्रियों के अधिकारों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर भी जोर दिया है। ऐसा खास तौर पर उड़ानों में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से मना किए जाने के मामलों के संदर्भ में कहा गया है। विमानन कंपनियों से कहा गया है कि वे इन अधिकारों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और हवाई अड्डा काउंटरों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

विमानन कंपनियों से यह भी कहा गया है कि वे यात्रियों के अधिकारों और सुविधाओं के बारे में क्षेत्रीय भाषाओं में स्पष्ट रूप से जानकारी दें ताकि लोगों तक पहुंच और जागरूकता बढ़ सके।

मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से यात्रियों को मदद मिलेगी, उनकी शिकायतें कम होंगी और पूरे विमानन क्षेत्र में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह सब ऐसे समय में किया जा रहा है जब उड़ान जैसी पहल के जरिये हवाई यात्रा का विस्तार तेजी से हो रहा है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS STANDARD DELHI 19 MARCH 2026

विमानन शेयरों पर दबाव, गिरावट बढ़ने की चेतावनी

निकिता वशिष्ठ
नई दिल्ली, 18 मार्च

भारत का विमानन क्षेत्र नई उथल-पुथल से जूझ रहा है। ईंधन की बढ़ती लागत,नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मुफ्त सीटों से जुड़े दिशानिर्देश और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संकट का अल्पावधि के आय परिदृश्य पर प्रभाव पड़ रहा है।

ऐस इक्विटी के आंकड़ों के अनुसार 2026 की शुरुआत से अब तक इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) और स्पाइसजेट के शेयरों में सेंसेक्स की 10 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले क्रमशः 13.97 प्रतिशत और 56.15 प्रतिशत की गिरावट आई है। विश्लेषकों का मानना है कि इन शेयरों के लिए सबसे बुरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है।

एमके ग्लोबल फाइनैंशियल सर्विसेज के विश्लेषकों ने कहा, 'ईरान युद्ध से बढ़ते तनाव ने पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र के बड़े हिस्से को 'नो-गो' जोन बना दिया है। इस कारण उड़ानों को रद्द करना और कई सेवाओं का मार्ग बदलना पड़ा है। उड़ान के समय में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण ईंधन की लागत में बढ़ोतरी अल्पावधि में एयरलाइनों के लाभ और मार्जिन पर भारी पड़ेगी।'

ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से एयरलाइन कंपनियों शेयरों में 18.9 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, जबकि सेंसेक्स 5.64 प्रतिशत नीचे आया है।

- ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से विमानन कंपनियों के शेयरों में 18.9 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, जबकि सेंसेक्स 5.64 प्रतिशत फिसला है
- विश्लेषकों ने आगाह किया कि तेल की कीमतों में तेज वृद्धि से इन कंपनियों के मार्जिन पर हो सकता है असर

ईंधन लागत बढ़ने से मार्जिन पर दबाव

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। भले ही कच्चे तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल के ऊंचे स्तर से घटकर 100 डॉलर रह गई हों, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि भविष्य की दिशा के बारे में अभी कुछ बताना कठिन है।

इंडिगो और एयर इंडिया सहित कई एयरलाइनों ने अपनी ओर से विभिन्न मार्गों पर 400 से 16,600 रुपये तक के ईंधन शुल्क लागू किए हैं। लेकिन स्वतंत्र बाजार विश्लेषक अंबरीश बालिगा का मानना है कि ईंधन शुल्क तेल की कीमतों में पूरी बढ़ोतरी की भरपाई नहीं कर पाएगा, जिससे अल्पावधि में आय की संभावना पर असर आएगा।

विश्लेषकों ने चेताया है कि तेल की कीमतों में इतनी तेज वृद्धि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के साथ साथ संभवतः वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भी मार्जिन पर असर डाल सकती है।

डीजीसीए के दिशानिर्देश से दबाव

डीजीसीए ने बुधवार को एयरलाइनों से 60 प्रतिशत सीटों को अतिरिक्त शुल्क से मुक्त रखने के लिए कहा। इससे सीट का चुनाव करने पर कमाई की उनकी क्षमता सीमित हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि ये दिशानिर्देश एयरलाइनों के सहायक राजस्व को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जो हाल के वर्षों में एयरलाइनों के मुनाफे में मददगार बन गया था।

इंडिगो, स्पाइसजेट: खरीदें या दूर रहें?

एक निवेश रणनीति के रूप में विश्लेषक निवेशकों को ईरान युद्ध समाप्त होने तक इन शेयरों से बचने का सुझाव दे रहे हैं।

खाड़ी क्षेत्र में कई अंतरराष्ट्रीय मार्ग, जो भारतीय वाहकों के लिए एक प्रमुख बाजार है, बाधित हो गए हैं। साथ ही, यात्रा सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता यात्रियों के मनोबल पर भारी पड़ने लगी है।

अंबरीश बालिगा ने कहा, 'छुट्टियों के मौसम से पहले, विशेष रूप से लीजर ट्रैवल पर असर पड़ने की संभावना है।'

उन्होंने सुझाव दिया कि निवेशकों को फिलहाल इन शेयरों से बचना चाहिए क्योंकि वित्तीय प्रभाव अगली कुछ तिमाहियों में महसूस किया जा सकता है। वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी निदेशक क्रांति बाथिनी ने कहा कि निवेशकों, विशेष रूप से अल्पावधि व्यापारियों को हालात सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS STANDARD DELHI 19 MARCH 2026

Govt curbs airline seat selection add-ons with 60% free mandate

DEEPAK PATEL
New Delhi, 18 March

THE CIVIL AVIATION MINISTRY DIRECTS CARRIERS TO SEAT PASSENGERS TRAVELLING ON THE SAME PNR TOGETHER, PREFERABLY IN ADJACENT SEATS

The Ministry of Civil Aviation on Wednesday asked airlines to allocate at least 60 per cent of seats on each flight free of charge and ensure that passengers with the same PNR number were allotted adjacent seats.

The move follows concerns raised by a Directorate General of Civil Aviation (DGCA) official that airlines and travel agents were using "dark pattern" techniques on their websites to nudge passengers into paying for seat selection during ticket booking or web check-in, while keeping the number of free seats very low. In several cases, passengers travelling together — on the same PNR number — were allotted separate seats if they did not pay, causing inconvenience.

The government's decision to mandate at least 60 per cent free seat allocation is likely to dent airlines' ancillary revenue streams, particularly those derived from paid seat selection. Seat-selection fee is one of the largest components of ancillary revenue, and carriers have increasingly leaned on such add-ons to bolster profitability.

The trend is evident in IndiGo's financial performance: Its ancillary revenue rose 13.6 per cent year-on-year (Y-o-Y) to ₹2,446.2 crore in the October-December quarter of FY26, outpacing the 6.2 per cent Y-o-Y growth in passenger ticket revenue to ₹20,464 crore.

Turn to Page 3

Airline stocks fly into rough weather 13

FROM PAGE 1

Govt curbs airline seat selection add-ons with 60% free mandate

The divergence reflects a broader industry strategy: While base airfares are often discounted to remain competitive, charges for services like seat selection tend to remain relatively stable, providing airlines with a cushion to protect margins.

In a statement, the ministry said India had become the world's third-largest domestic aviation market, with airports handling more than 500,000 passengers daily, emphasising the need for more passenger-friendly and uniform practices across airlines.

To address these concerns, the government has asked airlines to mandatorily provide "a minimum 60 per cent of seats on any flight to be allocated free of charge to ensure fair access".

It also directed carriers to seat passengers travelling on the same PNR together, preferably in adjacent seats, to avoid the current practice of splitting groups unless they opted for paid seat selection.

The ministry also said airlines must adopt transparent and passenger-friendly policies for carrying sports equipment, musical instruments, and pets, in line with safety and operational norms.

Additionally, it emphasised strict adherence to the passenger rights framework, particularly in cases of delays, cancellations and denied boarding, and asked airlines to prominently display these rights across their websites, mobile applications, booking platforms and airport counters.

Airlines have also been asked to clearly communicate passenger entitlements in regional languages to improve accessibility and awareness.

The ministry said the measures would benefit passengers, reduce grievances and ensure greater transparency across the aviation ecosystem, even as air travel continued to expand rapidly under initiatives such as UDAN.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS STANDARD DELHI 19 MARCH 2026

Airline stocks fly into rough weather again

Rising crude prices, free-seat rule cloud outlook for Indian carriers

NIKITA VASHISHT
New Delhi, 18 March

India's aviation sector is facing fresh turbulence, with rising fuel costs, the Ministry of Civil Aviation's free-seat directive, and geopolitical disruptions in West Asia clouding near-term earnings visibility.

Shares of SpiceJet and InterGlobe Aviation (IndiGo) have corrected 56.15 per cent and 13.97 per cent, respectively, since the start of 2026, against the Sensex's 10 per cent decline, according to Ace Equity. Analysts, however, caution that the worst may not be over yet.

"Escalating tensions in Iran-war-hit West Asia have rendered large parts of its airspace a 'no-go' zone, forcing flight cancellations and rerouting. Increased flight times, along with a spike in fuel costs due to rising crude oil prices, will weigh on airlines' profitability and margins in the near term," said analysts at Emkay Global Financial Services.

Since the Iran war began, airline shares have dropped up to 18.9 per cent, compared with a 5.64 per cent fall in the Sensex.

Going south

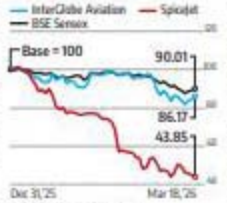

Sources: Bloomberg, BSE

Fuel bills blow a hole in profits

A sharp rise in global crude prices amid escalating West Asia tensions remains the sector's biggest overhang. While Brent crude has eased from $120 to $100 a barrel, analysts say uncertainty persists.

Airlines, including IndiGo and Air India, have introduced fuel surcharges ranging from ₹400 to ₹16,600 per route. Independent market analyst Ambareesh Baliga said, however, that these charges will not fully offset rising oil costs, clouding near-term earnings visibility.

Aviation turbine fuel, which tracks crude movements, has climbed to 85 per cent since the West Asia crisis began. Fuel accounted for 30-35 per cent of total operating expenses for IndiGo and SpiceJet at the end of the third quarter of financial year 2026 (Q3FY26). Analysts warn that such sharp cost increases could erode margins Q4FY26 and possibly Q1FY27.

Free seat rule clips airlines' wings

Adding to the pressure, the government asked airlines on Wednesday to keep 60 per cent of seats free of charge, limiting their ability to monetise from seat selection.

Analysts say the move could dent ancillary revenues, an increasingly critical profitability lever for carriers. "Seat pricing, a sizeable chunk of ancillary revenue, had been rising steadily. Freeing 60 per cent of seats will hurt realisations," Baliga said.

Chokkalingam G, founder and managing director of Equinomics Research, added that the government move, combined with rising fuel costs and reduced Gulf flights, is negative for the sector. "If this directive becomes permanent, it could kill the industry," he warned.

Airline stocks in a crosswind: Buy or bail?

Analysts advise investors to avoid these stocks until the Iran war subsides. Several international routes in the Gulf, a key market for Indian carriers, have been disrupted, while travel safety concerns are beginning to weigh on passenger sentiment.

"Leisure travel is expected to take a hit, especially ahead of the holiday season," Baliga said, recommending investors hold off as the financial impact unfolds over the coming quarters.

Kranthi Bathini, equity strategist at WealthMills Securities, said that while IndiGo's price-to-earnings valuations have corrected, they remain high at 37x. "Oil price movements will be the key monitorable, as margins are expected to stay under pressure in the near to medium term," he said.

Chokkalingam, however, believes much of the short-term pain may already be priced in, and long-term investors could consider buying the dip.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DAINIK BHASKAR DELHI 19 MARCH 2026

बदलाव : एक पीएनआर वाले साथ बैठ सकेंगे

एयरलाइंस पर लगाम: 60% सीटें मुफ्त चुन सकेंगे यात्री

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

घरेलू उड़ानों में यात्रियों को राहत देते हुए सरकार ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि फ्लाइट की कम से कम 60% सीटों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। अब तक केवल करीब 20% सीटें ही मुफ्त मिलती थीं, बाकी के लिए अलग से पैसे देने पड़ते थे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को बताया, डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को यह व्यवस्था लागू करने को कहा है, ताकि यात्रियों को सीट चुनने में बेहतर और निष्पक्ष सुविधा मिल सके। इसके साथ ही एयरलाइंस को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे यात्रियों को साथ बैठाया जाए।

नए निर्देश... अब परिवार के लोग पास-पास बैठ सकेंगे

मंत्रालय के अनुसार, परिवार या समूह के यात्रियों को संभव हो तो पास-पास सीट दी जाए। सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब एयरलाइंस द्वारा सीट चयन, बैगेज और अन्य सेवाओं के लिए बढ़ते शुल्क को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सीट चयन के अलावा खेल उपकरण, संगीत वाद्य यंत्र और पालतू जानवरों के परिवहन के लिए भी स्पष्ट और पारदर्शी नियम बनाए जाएंगे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DAINIK BHASKAR DELHI 19 MARCH 2026

बिजनेस एंकर यात्रा अब सिर्फ दूरी तय करने का माध्यम नहीं, बल्कि सुविधा और कम्फर्ट का खेल

युद्ध का असर, 'रिस्क फ्री ट्रेवल' के लिए दोगुना पैसे दे रहे पर्यटक; प्राइवेट जेट अमीरों की पहली पसंद, मालदीव में लैंडिंग 166% बढ़ी

भास्कर न्यूज | माले

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने लग्जरी ट्रैवल के एक नए ट्रेंड को जन्म दिया है। द्वीपीय देश मालदीव, जहां पहुंचने के लिए पर्यटकों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, वहां अब अमीर सैलानी सीधे प्राइवेट जेट्स से पहुंच रहे हैं।

मालदीव एयरपोर्ट्स कंपनी लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक, 28 फरवरी से 14 मार्च के बीच वहां प्राइवेट जेट लैंडिंग्स 166% बढ़ गई। पिछले साल जहां इस अवधि में 70 प्राइवेट जेट्स लैंड हुए थे, वहीं इस साल ये आंकड़ा 128 तक पहुंच गया है। 3 मार्च को तो एक ही दिन में रिकॉर्ड 18 जेट्स लैंड हुए।

मालदीव पहुंचने के लिए पर्यटकों को दुबई, दोहा या अबू धाबी जैसे हब एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन, इन शहरों के आस-पास भी हमले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जिन यात्रियों के पास ज्यादा पैसा है, वे प्राइवेट जेट लेकर सीधे मालदीव पहुंच रहे हैं। यह ट्रेंड बताता है कि यात्रा अब सिर्फ दूरी तय करने का माध्यम नहीं रही, बल्कि सुविधा और कम्फर्ट का खेल बन चुकी है। फ्लाइट्स में देरी और वापसी की अनिश्चितताओं से बचने के लिए अमीर यात्री 'रिस्क-फ्री ट्रैवल' को प्राथमिकता दे रहे हैं।

बहरहाल, ब्रिटेन से मालदीव जाने वाली सीधी उड़ानों का किराया हाल के दिनों में काफी बढ़ गया है। लंदन से मालदीव की राजधानी माले के बीच 4-11 अप्रैल के लिए रिटर्न टिकट्स अब 3.7 लाख रुपए में मिल रहे हैं, जो सामान्य से ज्यादा है। प्राइवेट जेट ऑपरेटर्स और लग्जरी टूरिज्म सेक्टर इसका फायदा उठा रहे हैं। आमतौर पर सिर्फ अमीर ग्राहकों पर निर्भर रहने वाली प्राइवेट एविएशन इंडस्ट्री की मांग अचानक बढ़ गई है। साथ ही मालदीव जैसी पर्यटन-आधारित इकोनॉमी के लिए मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव अवसर बनकर उभरा है। ज्यादा खर्च करने में सक्षम पर्यटक सीधे वहां पहुंच रहे हैं।

बदले हुए हालात में एयरलाइंस के लिए भी रणनीति बदलना मजबूरी

मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव ने कमर्शियल एयरलाइंस को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। एयरलाइंस मालदीव के लिए सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ा रही हैं। एयर इंडिया ने 10-18 मार्च के बीच मालदीव समेत अन्य नजदीकी देशों के लिए 78 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ी हैं। रूस की एयरोफ्लोट ने भी मॉस्को से माले, फुकेत, बैंकॉक और कोलंबो जैसे प्रमुख एशियाई पर्यटन स्थलों के लिए उड़ानें बढ़ाई हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DAINIK BHASKAR DELHI 19 MARCH 2026

एअर इंडिया ने अपने सभी 30 ग्राउंडेड विमान सुधारे

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

एअर इंडिया ने निजीकरण के समय मिले सभी 30 ग्राउंडेड विमान सेवा में बहाल कर दिए हैं। अब एयरलाइन के एक्टिव बेड़े में 186 विमान हैं। टाटा ग्रुप ने 2022 में कमान संभालते ही बेड़े को दुरुस्त करने को प्राथमिकता दी थी। आखिरी विमान वीटी-एएलएल फरवरी 2020 से स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण खड़ा हुआ था। नागपुर एमआरओ में इसके 4000 मेंटेनेंस टास्क पूरे किए गए। 3,000 से ज्यादा नए पुर्जे और दोनों इंजन बदले गए। निजीकरण के वक्त एयरलाइन के पास 110 विमान थे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DESHBANDHU DELHI 19 MARCH 2026

सुविधा

डीजीसीए ने सभी विमान सेवा कंपनियों को दिए निर्देश

फ्लाइट में एक ही पीएनआर पर साथ-साथ मिलेगी सीट

नई दिल्ली, 18 मार्च (एजेंसियां)। एक ही पीएनआर पर बुक कराए गए टिकट पर अब यात्रियों को फ्लाइट में एक साथ सीट देना अनिवार्य कर दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी विमान सेवा कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कम से कम 60 प्रतिशत सीटों का आवंटन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के करना अनिवार्य होगा।

■ 60 फीसदी सीटें निशुल्क चयन के लिए उपलब्ध कराई जाएं

साथ ही एक ही पीएनआर पर बुक कराए गए टिकट के लिए यात्रियों को एक साथ सीट देनी होगी, जहां तक संभव हो उन्हें अगल-बगल की सीट प्रदान करने के लिए कहा गया है। आमतौर पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें एक ही परिवार के लोगों को एक ही पीएनआर पर बुक कराये गए

टिकट पर काफी दूर-दूर बैठने के लिए सीट आवंटित की जाती थी जिससे लोगों को परेशानी होती थी। एयरलाइंस एक साथ पसंदीदा सीट के चयन पर मोटा शुल्क वसूलती थीं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि उसने डीजीसीए के माध्यम से यह निर्देश जारी किया है ताकि यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके। यह यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के उसके सतत प्रयासों का एक हिस्सा है। निर्देश में कहा गया है कि सुरक्षा और परिचालन संबंधी नियमों का ध्यान रखते हुए खेल उपकरणों और वाद्य यंत्रों को फ्लाइट में ले जाने के लिए पारदर्शी और यात्री-अनुकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे पालतू जानवरों को फ्लाइट में ले जाने के बारे में भी स्पष्ट और पारदर्शी नीति तैयार करें।

यात्रियों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से दिखाएं

विमान सेवा कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप, अन्य बुकिंग प्लेटफॉर्म और हवाई अड्डों पर मौजूद उनके काउंटरों पर यात्रियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। निर्देश दिया गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी यात्रियों के अधिकारों की उन्हें जानकारी प्राप्त जानकारी दी जाए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DECCAN HERALD BANGALORE 18 MARCH 2026

IndiGo to stop S'mogga-B'luru flight service

SHIVAMOGGA, DHNS: In accordance with the guidelines of the DGCA, IndiGo Airlines has decided to temporarily suspend flights between Shivamogga and Bengaluru from May 1 due to shortage of pilots.

The company said it will suspend operations for 3 months. Since monsoon starts in mid-May, it is the off-season period. Passengers will not be affected much, he added. After the crash of an Air India flight in Ahmedabad on June 12, 2025, DGCA has formulated some rules for safety of flights.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DECCAN HERALD BANGALORE 18 MARCH 2026

MAJOR CHALLENGE

Global airlines hike fares, cut routes as fuel costs balloon

Conflict disrupts global aviation, affects routes and operations

REUTERS

Global airlines sounded the alarm on Tuesday over soaring jet fuel prices triggered by the US-Israeli war against Iran, warning of hundreds of millions of dollars in additional costs, higher fares and cuts to some routes.

Delta Air Lines Chief Executive Ed Bastian said the sharp rise in jet fuel prices had increased the airline's costs by as much as USD 400 million in March alone. The industry is moving quickly to pass on higher expenses through fare hikes, he told a J.P. Morgan industrials conference.

American Airlines said it expects a USD 400 million increase in first-quarter expenses due to fuel costs. Among the first to act, Scandinavia's biggest airline, SAS AB, said it is cutting a limited number of flights because of the "sharp and sudden increase" in fuel prices.

"The entire European aviation system is now feeling the pressure from a sudden fuel shock," it said in an email.

The war, now in its third week, has thrown global aviation into turmoil, with flights cancelled, rescheduled or rerouted as most West Asia airspace remains closed amid fears of missile and drone attacks. Jet fuel prices have emerged as a major challenge, pushing up operating costs, with European prices doubling and Asian prices rising by almost 80 per cent since the start of US and Israeli strikes on Iran in late February.

Fuel is the industry's second-largest expense after labour, typically accounting for a fifth to a quarter of operating costs. US airlines largely stopped hedging fuel in the past two decades, and SAS said last year it had not hedged any of its fuel consumption for the following 12 months. Vietnamese authorities have warned the country's aviation industry to prepare for potential flight reductions from April after China and Thailand halted jet fuel exports due to the war, heightening the risk of shortages.

The United Arab Emirates briefly closed its airspace on Tuesday in response to incoming missile and drone threats from Iran, the second consecutive day of disruption after a drone caused a fire near Dubai airport on Monday.

About 86,000 passengers travelling through Frankfurt Airport, one of Europe's largest, were affected by cancellations in the first two weeks of the war. Only one-third of weekly connections between the airport and West Asia are operating now, CEO Stefan Schulte said on Tuesday.

The mounting cost warnings show how the shockwaves from the conflict are spreading far beyond West Asia as airlines navigate their biggest crisis since the COVID pandemic. Delta's Bastian said the carrier is well positioned to recover fuel costs and can adjust capacity if elevated prices persist. Still, airlines will need to tread carefully with fare hikes at a time of fragile consumer confidence.

Air France-KLM announced plans last week to increase long-haul ticket prices to offset surging fuel costs.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DAINIK JAGRAN DELHI 19 MARCH 2026

बिना अतिरिक्त शुल्क 60% सीटें दें एयरलाइनें

- डीजीसीए ने घरेलू उड़ानों के लिए जारी किए नए नियम
- एक ही पीएनआर वाले यात्रियों को साथ बैठाने पर जोर

यात्रियों की सुविधा को और मजबूत करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। अब सीट शुल्क, परिवार के साथ बैठने की व्यवस्था और विभिन्न सेवाओं के लिए स्पष्ट नियम लागू होंगे। - के. राममोहन नायडू, नागर विमानन मंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: हवाई यात्रियों को राहत देते हुए सरकार ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि घरेलू उड़ानों में कम से कम 60 प्रतिशत सीटों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए। साथ ही एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों, खासकर परिवार को साथ बैठाने के लिए भी कहा गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के माध्यम से एयरलाइनों को यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इससे टिकट बिक्री के बाद सीट आवंटन करके अतिरिक्त धन कमाने की एयरलाइनों की प्रवृत्ति पर लगाम लगने की संभावना है।

मौजूदा व्यवस्था में केवल करीब 20 प्रतिशत सीटें ही बिना शुल्क के उपलब्ध होती हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यात्री सुविधाएं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, मंत्रालय ने यात्रा को और आसान बनाने के लिए कई यात्री-केंद्रित पहल शुरू की हैं, जिनमें किफायती भोजन के लिए उड़ान यात्री कैफे, किताबों तक मुफ्त पहुंच के लिए फ्लाईब्रेरी व हवाईअड्डों पर मुफ्त वाई-फाई की व्यवस्था शामिल है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उड़ान में देरी, रद्दीकरण या बोर्डिंग से इन्कार की स्थिति में यात्री अधिकारों का सख्ती से पालन किया जाए। इन अधिकारों की जानकारी एयरलाइनों की वेबसाइट, मोबाइल एप, बुकिंग प्लेटफार्म और एयरपोर्ट काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

RS DAINIK JAGRAN DELHI 19 MARCH 2026

घरेलू उड़ानों में 60% सीटें बगैर अतिरिक्त शुल्क के दें एयरलाइनें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अभी 20 प्रतिशत सीटें ही बगैर शुल्क होती हैं उपलब्ध
- डीजीसीए ने घरेलू उड़ानों के लिए जारी किए नए नियम

हवाई यात्रियों को राहत देते हुए सरकार ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि घरेलू उड़ानों में कम से कम 60 प्रतिशत सीटों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए। इसके साथ ही एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों, खासकर परिवार के सदस्यों को साथ बैठाने के लिए भी कहा गया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में घोषणा करते हुए बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के माध्यम से एयरलाइनों को यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं। टिकट बिक्री के बाद सीट आवंटन करके अतिरिक्त धन कमाने की एयरलाइनों की प्रवृत्ति पर इससे लगाम लगने की संभावना है।

मौजूदा व्यवस्था में केवल करीब 20 प्रतिशत सीटें ही बिना शुल्क के उपलब्ध होती हैं, जबकि बाकी सीटों के चयन के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यात्री सुविधाएं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।

इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप, मंत्रालय ने यात्रा को और आसान बनाने के लिए कई यात्री-केंद्रित पहल शुरू की हैं, जिनमें किफायती भोजन के लिए उड़ान यात्री कैफे, किताबों तक मुफ्त पहुंच के लिए फ्लाईब्रेरी तथा हवाई अड्डों पर मुफ्त वाई-फाई की व्यवस्था करना भी शामिल है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE ECONOMIC TIMES DELHI 19 MARCH 2026

FLIGHT OF YOUR FANCY

Now, Choose a Seat without Charge

Ministry directs airlines to remove selection fee from at least 60% plane seats; DGCA order awaited

Our Bureau

Mumbai | New Delhi: India has mandated airlines to offer up a majority of seats for choice without additional charges and seat passengers on the same booking together, a move that experts said could push airlines to raise base fares.

The ministry of civil aviation on Wednesday said it has issued directions through the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) requiring all Indian airlines to make "at least 60% of seats" on every flight free of selection charges and ensure passengers on a common PNR be preferably seated on adjacent seats.

A formal order operationalising the directive was yet to be issued as of press time. A government official said DGCA will bring enabling provisions in the next few days.

The move is in response to increasing complaints from travellers over difficulty in getting free seats, and family members having to pay for seats to ensure they are seated together.

However, it impacts a key ancillary revenue stream for carriers, which helps airlines to keep the base fare low in one of the world's most price-sensitive aviation markets, experts said. "India already has some of the lowest airfares globally, supported by ancillary revenues," said Vishok Mansingh, chief executive of Vman Aviation consultancy and leasing company.

Legal or Not? ▸▸ 9

Legal or Not?

▸▸ From Page 1

"Restricting these will push up pure vanilla (base) fares, ultimately hurting price-sensitive travellers who just want affordable point-to-point travel," warned Mansingh of Vman.

There is also a question over the legality of the move.

The current regulations, which came in 2014, permit airlines to charge separately for items like preferential seats, bags, and meals. Airlines are free to fix charges. DGCA can only intervene if airlines are found to violate principles of transparency and discrimination.

Also, in 2017, the Delhi High Court ruled that the regulator cannot determine the tariff for a specified flight product; it has to be determined by market forces.

The official cited above, however, contended that the government is not mandating any pricing for airlines but instead pushing the airlines to keep a certain portion of the seats free. "We are not in favour of interfering in commercial matters of airlines, but the government has to address it if a large section of the public complains," he said.

Passengers currently have the option to skip preferred seat selection, in which case the airlines assign a seat two hours before the departure. However, in many cases, passengers travelling together are seated separately unless they pay for preferred seats.

RECOVERING COSTS

"Ensuring passenger rights is very important, but it is equally important to balance the commercial interests of airlines, especially as Indian carriers remain structurally unprofitable," said Kapil Kaul, chief executive and director of CAPA India, an aviation consultancy firm. "Ancillary revenues are key to profitability. Any regulatory action that impacts pricing must be studied in detail, otherwise we could see higher fares."

Kaul said Indian carriers are likely to post around $2.5 billion losses for FY26. In FY25, 10% of IndiGo's total revenue came from such sources, as compared to the global average of around 16%.

Shares of InterGlobe Aviation, which operates IndiGo, however, didn't react to the development and closed 1.71% higher at Rs 4,361.10 on the NSE on Wednesday as analysts expect that the airline will be able to recover the cost from higher fares.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE ECONOMIC TIMES DELHI 19 MARCH 2026

HC Rejects SpiceJet's Offer to Deposit Title Deed as Security

Indu Bhan

New Delhi: The Delhi High Court on Wednesday rejected SpiceJet's offer to submit an "unencumbered" land property as security instead of depositing ₹144 crore with the court registry in an arbitration award dispute with former promoter Kalanithi Maran and his KAL Airways.

A single judge bench of Justice Subramonium Prasad has now asked the cash-strapped airline to deposit the amount in cash within four weeks.

"We have suffered losses, have a liquidity issue" as various flights to the Gulf have been cancelled due to the recent West Asia conflict, senior counsel Amit Sibal, appearing for SpiceJet, told the court. "Net worth is not negative, but we are submitting 4,000 sq ft of land of equivalent value" instead of cash payment of ₹144 crore, he said.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE FINANCIAL EXPRESS DELHI 19 MARCH 2026

60% of flight seats to be free of cost

YARUQHULLAH KHAN
New Delhi, March 18

THE DIRECTORATE GENERAL of Civil Aviation (DGCA) on Wednesday directed airlines to make at least 60% of seats on all domestic flights available free of any additional charge and to seat passengers on the same booking reference together, preferably in adjacent seats.

The order follows a rise in passenger complaints over limited free seat availability during web check-ins and sustained pressure from consumer groups and the ministry of consumer affairs. The ministry had flagged the issue in October 2023, terming the practice of marking most seats as paid an unfair trade practice under the Consumer Protection Act and describing such design tactics as dark patterns.

Passenger feedback pointed to airlines offering only a handful of seats without any extra charges, often middle seats at the rear, while levying additional charge for most others. Families had flagged instances of being separated unless they paid extra. While the DGCA mandated in April 2024 that children under 12 be seated with at least one parent at no additional cost, the new directive extends the principle to all passengers on the same PNR.

Industry estimates indicate that currently about 20% of seats come without any additional levy, with the rest priced based on location and features. "The move to eliminate fees on 60% of seats improves transparency and fairness," Vandana Singh, chairperson, aviation cargo, Federation of Aviation Industry in India, said.

Continued on Page 7

60% of flight seats to be free of cost

THE DIRECTIVE IS expected to impact ancillary revenues from seat selection. Shares of IndiGo and SpiceJet pared early gains to trade lower after the announcement. Analysts said the order could add pressure on an industry where most carriers, barring IndiGo, remain loss-making.

Lokesh Sharma, an aviation and defence analyst, said the change could reduce ancillary income, especially if window seats are included in the free quota. He noted that airlines typically offer 12–15 free seats on a 186-seat aircraft, or about 8% of capacity, with the rest priced between ₹468-855.

Airlines said the impact may be limited as passengers usually pay for window or extra legroom seats, which can continue to be charged. The DGCA has not specified which seats must be free. The regulator also asked airlines to publish standardised policies for carrying pets, musical instruments and sports equipment, and to display passenger rights on delays and cancellations in regional languages. The civil aviation ministry said the focus remains on passenger facilitation and uniform practices across carriers.

The civil aviation ministry said the focus remains on passenger facilitation and uniform practices across carriers

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

FREE PRESS JOURNAL MUMBAI 18 MARCH 2026

Rust to flight: Nagpur MRO completes AI's 777 revival

FPJ News Service
MUMBAI

The Air India Engineering Services Ltd (AIESL) MRO facility in Nagpur successfully completed an intensive, nose-to-tail restoration of VT-ALL, marking the end of a massive fleet revival project. The aircraft entered the Nagpur facility in May 2025 to undergo a full systems rebuild after being grounded for over six years.

Skilled engineering teams at the Nagpur base worked nearly round the clock to replace major assemblies, including engines and landing gear, essentially reconstructing the aircraft's functional backbone. This final restoration in Nagpur signifies the airline's successful effort to return every one of its 30 previously grounded aircraft to service.

The Boeing 777-300ER was originally grounded in February 2020 due to multiple unserviceable systems and ageing components. Since returning to the Tata Group in 2020, Air India has prioritised rebuilding its legacy fleet of 113 aircraft. Post-privatisation, the airline committed significant resources to revive 30 wide-body and narrow-body planes that had remained untouched for years.

The restoration was a feat of high complexity, involving the installation of over 3,000 new key components and the completion of over 4,000 maintenance tasks. The process included replacing inlet and fan cowls, thrust reverser cowls, and the APU. Every structural repair and part replacement underwent stringent testing and documentation under the regulatory oversight of the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), with technical guidance from Boeing.

VT-ALL completed its test flight on March 6 and has met all safety compliances. The airline confirmed it has received the airworthiness review certificate (ARC), the mandatory certification required to commence regular operations. An Air India spokesperson stated that the operational status of these 30 aircraft proves India's growing capabilities in complex aircraft maintenance and engineering excellence.

In the next phase, starting 2027, VT-ALL and the other B777 aircraft in Air India's fleet will undergo a full retrofit in the next phase. The aircraft will offer the new Air India experience with new seats and modern amenities while sporting new livery.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

FREE PRESS JOURNAL MUMBAI 18 MARCH 2026

taking wing

AI's Boeing 777 restored after 6 yrs on ground

PTI
NEW DELHI

After being grounded for over six years, Air India's legacy Boeing 777-300ER aircraft has started flying again.

More than 3,000 new key components were installed and over 4,000 maintenance tasks were completed as the Tata Group-owned airline restored the wide-body aircraft , with all the works done at the AI Engineering Services Limited (AIESL) facility in Nagpur.

The aircraft VT-ALL was grounded in February 2020 due to multiple unserviceable systems and ageing components, Air India said in a statement on Tuesday.

The decision to restore the plane was taken in April 2025.

The loss-making Air India was acquired by the Tata Group from the government in January 2022.

"In April 2025, Air India initiated efforts to bring it back to full operational life to support long haul expansion. The aircraft entered the AIESL Nagpur MRO facility in May 2025, beginning an intensive, nose-to-tail restoration programme," the statement said.

MRO refers to Maintenance, Repair and Overhaul.

"Among the inherited legacy fleet of 113 aircraft were 30 wide-body and narrow-body aircraft that had remained long grounded and untouched for years...," Air India said and added that VT-ALL was the last of the 30 grounded aircraft back in service.

Currently, Air India has a fleet of nearly 190 narrow-body and wide-body planes.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

FREE PRESS JOURNAL MUMBAI 18 MARCH 2026

Flights cancelled, delayed as US storms dump snow

AP
ATLANTA

Hundreds of flights were cancelled or delayed on Tuesday, one day after powerful storms swept across the eastern half of the country and upended air travel in a cross-section of cities.

Travellers have been facing additional jams at airport security checkpoints as a partial government shutdown strains screener staffing.

The disruptions come at an already challenging time for air travel, in part because the shutdown that began February 14 has pressured staffing at some security checkpoints.

At the same time, airports are crowded with spring break travellers and fans heading to March Madness games, the annual NCAA men's and women's college basketball tournaments.

More than 750 flights scheduled to fly into, out of or within the US have been called off as of early Tuesday, and about 1,300 were delayed, according to flight-tracking site FlightAware.

Flight delays and cancellations piled up Monday at some of the nation's largest airports, including those in New York, Chicago and Atlanta.

The storm system that dumped heavy snow across the Midwest raced toward the East Coast with high winds reaching gusts near 50 mph (80 km) in parts of New York, the National Weather Service said.

Kelly Price, who was trying to get home to Colorado after a family vacation in Orlando, Florida, said her Sunday night flight wasn't cancelled until early Monday.

"By that time the only place for us to sleep was the airport floor. So we're all tired and frustrated," she said, adding that the soonest she and her family could book another flight doesn't leave until Tuesday afternoon.

Impact to major airport hubs The nationwide cancellations on Monday included about 600 in and out of Chicago O'Hare International, more than 470 at Atlanta's Hartsfield-Jackson International and over 450 at LaGuardia Airport in New York City, according to FlightAware.

Citing severe weather, the Federal Aviation Administration ordered ground stops at Hartsfield-Jackson and Charlotte Douglas International Airport and ground delays at JFK and Newark Liberty International Airport.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

HARI BHUMI DELHI 19 MARCH 2026

एयरलाइंस के मनमानी चार्ज पर लगेगी लगाम

सरकार ने 60% सीटें फ्री रखने का विमानन कंपनियों को दिया आदेश

एजेंसी ▸▸ नई दिल्ली

सरकार ने विमानन कंपनियों से घरेलू उड़ानों में 60 प्रतिशत सीट पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क न लेने को कहा है। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय के प्रयासों के तहत यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए विमानन कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि एक ही 'पीएनआर' (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को उड़ान में साथ बैठाया जाए। इन कदमों की घोषणा करते हुए मंत्रालय ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि हर उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीट बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं ताकि निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित हो सके।

केवल 20 प्रतिशत सीट बिना शुल्क के बुक

विमानन कंपनी के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में केवल 20 प्रतिशत सीट बिना शुल्क के बुक की जा सकती हैं जबकि बाकी सीट के लिए भुगतान करना पड़ता है। मंत्रालय ने कहा, ' एक ही 'पीएनआर' पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ बैठाया जाए या आस-पास की सीट दें। अधिकारी ने बताया कि ये निर्देश घरेलू उड़ानों पर लागू होंगे। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब सीट चयन सहित विभिन्न सेवाओं के लिए विमानन कंपनियों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

परिवारों के लिए साथ बैठने की व्यवस्था

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी दी कि यात्रियों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा,' 60 प्रतिशत सीट बिना शुल्क, परिवारों के लिए साथ बैठने की व्यवस्था और खेल उपकरण, संगीत वाद्ययंत्र एवं पालतू जानवरों के परिवहन के लिए स्पष्ट तथा पारदर्शी नियम।' मंत्री ने बताया कि देरी और टिकट रद्द कराने की स्थिति में भी यात्री अधिकारों के प्रवर्तन को मजबूत किया जाएगा।

हर जगह दिखेंगे यात्रियों के अधिकार

अब एयरलाइंस को अपने वेबसाइट, मोबाइल ऐप, टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर यात्रियों के अधिकार स्पष्ट रूप से दिखाने होंगे। साथ ही इन जानकारियों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ सकें।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

HINDUSTAN DELHI 19 MARCH 2026

विमान की 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क देनी होंगी

- यात्रियों की सुविधा के लिए डीजीसीए का आदेश
- अभी 20% सीटों पर नहीं लगता है अतिरिक्त शुल्क

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। हवाई यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं देने के उद्देश्य से नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कई अहम बदलाव किए हैं। इसी कड़ी में अब किसी भी घरेलू उड़ान में 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवंटित करनी होंगी।

इसके अलावा एक ही पीएनआर पर सफर करने वाले यात्रियों को एक साथ या संभव न हो तो पास-पास सीट देनी होगी। अभी तक विमानन कंपनियां एक पीएनआर पर अगर दो या उससे अधिक यात्रियों की टिकट बुक है तो उसमें से एक ही व्यक्ति को निःशुल्क सीट चुनाने का अवसर देती हैं, बाकी सीटें अलग-अलग आवंटित की जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति परिवार के साथ यात्रा करता है तो उसे आसपास की सीट खरीदनी पड़ती है मगर नए प्रावधानों के तहत विमानन कंपनियों को साथ में सीट देनी होगी। अगर बराबर की सीट उपलब्ध नहीं है तो फिर आसपास में सीट देनी होगी। इस फैसले से हर रोज बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ होगा। अभी विमानन कंपनियों द्वारा 20% सीटें बिना शुल्क के आवंटित की जाती हैं, लेकिन अब यह प्रतिशत बढ़कर 60 हो गया है। बड़ी संख्या में यात्रियों को इसका लाभ होगा।

स्थानीय भाषा में जानकारी P13

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

HINDUSTAN DELHI 19 MARCH 2026

एयर इंडिया 48 उड़ानों का संचालन करेगी

नई दिल्ली। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस गुरुवार को पश्चिम एशिया के लिए कुल 48 उड़ानों का संचालन करेंगी। एयर इंडिया के आधिकारिक बयान के अनुसार, गुरुवार को कुल 48 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 16 नियमित और 32 विशेष उड़ानें शामिल होंगी, जो दुबई के लिए भी उपलब्ध रहेंगी। उधर, आयरलैंड के शैनन शहर में दो दिनों से अधिक समय से फंसे यात्रियों को लेकर एअर इंडिया की एक विशेष उड़ान बुधवार दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हुई।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

HINDUSTAN DELHI 19 MARCH 2026

यात्रियों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी देनी होगी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। विमान यात्रियों की सुविधा के लिए डीजीसीए ने कई स्तर पर अन्य बदलाव भी किए हैं, जिससे यात्रा के दौरान लोगों को कोई असुविधा न हो। इसके लिए विमानन कंपनियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह यात्रियों के अधिकारों की स्पष्ट जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में दें।

मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यात्री अनुभव को बेहतर बनाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, शिकायतों को कम करने और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की दिशा में सभी फैसले लिए गए हैं। जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि खेल उपकरण और संगीत वाद्ययंत्रों के परिवहन को पारदर्शी और यात्री-अनुकूल तरीके से सुविधा प्रदान की जाए, जो सुरक्षा और संचालन संबंधी नियमों के अधीन हो।

डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइंस पालतू जानवरों के परिवहन के लिए स्पष्ट नीति बनाएंगी। यात्रियों के अधिकारों का कड़ाई से पालन करना होगा। विशेष रूप से विमान के विलंब से पहुंचने, रद्द होने व बोर्डिंग से इनकार किए जाने की स्थिति में यात्रियों को स्पष्ट जानकारी देनी होगी। एयरलाइंस की वेबसाइट, ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और हवाई अड्डा काउंटरों पर यात्री अधिकारों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE HINDUSTAN TIMES DELHI 19 MARCH 2026

AIRLINES RESUME FLIGHTS TO DUBAI AFTER CURBS END

NEW DELHI: Indian airlines on Wednesday began resuming services to Dubai, after the city's authorities lifted a bar on foreign carriers landing at the international airport, services at which have been hobbled since a drone strike on Monday.

Air India and Air India Express detailed plans to fly jets to Dubai International Airport, the world's busiest aviation hub for international flights after an update from the civil aviation authority. IndiGo said it resumed those services at 4pm Dubai time on Wednesday. The airlines did not specify the number of flights that would make the trip.

The airport on Monday evening suspended landings for all foreign carriers hours after a drone struck a fuel tank at the complex.

Air India and Air India Express will operate 48 scheduled and non-scheduled flights to and from West Asia on (Thursday).

IndiGo, in a statement on X, said: "Following the latest update from the Dubai Civil Aviation Authority, flight operations to and from Dubai have resumed with effect from 1600 hrs (DXB local time) on 18 March 2026."

Akasa Air said it would progressively restore select services in West Asia. "Starting today (Wednesday), flights will begin operating to/from Riyadh and Mumbai," the airline said on X. PTI

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE HINDUSTAN TIMES DELHI 19 MARCH 2026

Airlines must offer 60% seats without extra fees

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Airlines must allocate 60% of seats on a flight without additional selection charges while ensuring that passengers on the same booking are grouped together, the civil aviation ministry said on Wednesday in a stack of directions aimed at bulking up passenger rights and curbing arbitrary carrier practices.

Orders that cement these directions will be issued on Thursday, people aware of the matter said.

"To further strengthen passenger convenience, transparency and uniformity of practices across airlines, the Ministry has issued directions through the DGCA... a minimum of 60% of seats on any flight to be allocated free of charge to ensure fair access."

Indian airlines charge passengers an ancillary fee to book seats of their choice during the web check-in process. For instance, a bulk of the 180 seats on a jet like the Airbus A320 need to be paid for, over and above the ticket price, on a scale. Seats towards the front of the aircraft and window seats are usually costlier.

Between 5% and 15% of seats on a flight do not have an ancillary charge.

To be sure, these charges are not applicable for checkins at the airport.

It also directed airlines to ensure that passengers travelling on the same PNR code should be seated together. ISTOCKPHOTO

The steps are being taken as part of a broader push to standardise services across the sector, the government said on Wednesday. It also directed airlines to ensure that passengers travelling on the same PNR (Passenger Name Record) code should be seated together, "preferably in adjacent seats."

"Carriage of sports equipment and musical instruments to be facilitated in a transparent and passenger-friendly manner, subject to applicable safety and operational regulations. Airlines shall also bring out clear, transparent policies for carriage of pets," said the ministry statement.

The government also directed airlines to strictly adhere to the passenger rights framework, particularly in cases of delays, cancellations and in instances where fliers were not allowed to board.

Experts however said Wednesday's directions were vaguely worded and may leave the door open for airlines to charge passengers for the remaining 40% seats even for check-ins at the airport.

"The directive is a bit confusing at this stage. Conceptually, if a passenger has not checked-in online and decides to do it after reaching the airport, considering that he definitely wouldn't fall under the 60% criteria, they may be asked to pay for the seat," an industry insider said.

Others said the order would slash revenue for jets.

A former bureaucrat said, "This directive is a dent in revenue for a flight with low load factor. For instance, if the load factor of a flight is 65% then it's a loss to that airline, since charging money for selecting seats is a hot selling revenue option for them."

MOCA also directed airlines to have a prominent display of passenger rights across airline websites, mobile applications, booking platforms, and airport counters.

It also asked them to have a clear communication of passenger entitlements in regional languages to ensure wider accessibility and awareness.

The directions come at a time when India has emerged as the world's third-largest domestic aviation market, with airports handling over 500,000 passengers every day.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE HINDUSTAN TIMES DELHI 19 MARCH 2026

PHOTOS: ADOBE STOCK(FOR REPRESENTATIONAL PURPOSE ONLY)

Travellers welcome new DGCA regulations, seeing these as a long-overdue shift toward prioritising passenger rights

NEW RULE: 60% FLIGHT SEATS AT NO ADDITIONAL COST

Families get split unless they pay for seats. I've faced it too, and it's a real frustration for most flyers. This finally addresses a long-standing issue, making travel smoother for both passengers and cabin crew. You can debate pricing, but sitting with your family shouldn't be a premium feature.

ANMOL SACHAR, CONTENT CREATOR

As cabin crew, we often deal with families seated apart, it's tough to manage their requests during hectic boarding phase. The new norms are a welcome change. They may not end last-minute requests, but will reduce them, letting us focus on safety and service. It's a win-win: smoother boarding, happier passengers, less stress for us.

DIYA TANEJA, CABIN CREW

There have been times where we have received our instruments at airports in damaged condition... What this DGCA regulation does most importantly is that it brings us closer to ensuring that our stuff is being taken care of.

SUBIR MALIK, MUSICIAN

Addressing frequent flyers' concerns, the Ministry of Civil Aviation, through the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), introduced new passenger-friendly rules on Wednesday. The press release stated that "passenger facilitation remains its highest priority".

With India now the "third-largest domestic aviation market globally", the guidelines aim to improve travel ease through initiatives like UDAN Yatri Cafés for affordable food, Flybrary for free books, and complimentary airport Wi-Fi.

The move is being hailed as a "welcome change" by airline professionals as well as performing artistes especially musicians who have faced challenges while travelling with their instruments.

Inputs by Navya Sharma, Deep Saxena and Karan Sethi

What's new?

- **Free seat allocation**: Airlines will be required to make at least 60% of seats available at no additional cost.
- **Family Seating**: Passengers under a single PNR should be seated together to avoid separating families.
- **Pet/Equipment Policy**: Airlines must have clear, passenger-friendly policies for transporting sports gear, musical instruments, and pet travel, in line with safety norms.
- **Strict compliance with Passenger Protection Norms**: Airlines are expected to adhere closely to established passenger rights, especially in situations involving flight disruptions such as delays, cancellations, or denied boarding.
- **Multilingual communication**: To improve accessibility, airlines must communicate passenger entitlements in regional languages in addition to English, making information easier to understand for a wider audience.
- **Visibility of Information**: Passenger rights must be clearly displayed across all touchpoints—websites, apps, booking portals and airport counters, to keep travellers well-informed.

Rules need to be strict as airlines don't own up anything. In August 2022, my accompanist Giridhar Udupa had his ghatam broken on a Bengaluru–Delhi flight. Only after the tweet went viral did they offer a refund voucher. I've also been downgraded from business class thrice without notice, facing rude behaviour, resolved only after tweeting. Imagine what common passengers go through. This is a welcome move.

RICKY KEJ, GRAMMY-WINNING MUSICIAN

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE INDIAN EXPRESS DELHI 19 MARCH 2026

Keep 60% seats free of selection fee; can sit together if PNR is same : Govt

DGCA issues directions to all Indian carriers

Sukalp Sharma
New Delhi, March 18

Airlines were asked to ensure strict adherence to the passenger rights framework, particularly in cases of delays, cancellations. EXPRESS FILE

THE DIRECTORATE General of Civil Aviation (DGCA) has directed airlines to ensure that at least 60% of seats on flights are offered without any selection fee, and passengers on the same booking reference, or PNR, are seated together, "preferably in adjacent seats".

Passengers have long complained that airlines offer very few free-of-charge seats for pre-selection and during web check-in. For groups or families travelling on the same PNR, not being able to sit together, particularly if children are part of the group, has also been a major grouse.

"To further strengthen passenger convenience, transparency and uniformity of practices across airlines, the Ministry has issued the following directions through the Directorate General of Civil Aviation (DGCA): Minimum 60% of seats on any flight to be allocated free of charge to ensure fair access, passengers travelling on the same PNR to be seated together, preferably in adjacent seats...," the Ministry of Civil Aviation (MoCA) said in a release.

Flyers have been complaining that the few seats airlines offer free of charge during booking or web check-in are often middle seats or seats at the rear of the cabin. Usually though, better seats can be availed at the airline's check-in counter at the airport prior to departure for free, subject to availability. But that option isn't really available if the flight is full. Most Indian airlines currently offer a limited number of seats, usually 20-30%, for free during booking and web check-in, while charging selection fee for others; the charges can vary depending on factors like the location of the seat in the aircraft cabin and in the specific row, and seat pitch, which effectively is a measure of leg-room. Also, all seat selection — chargeable and free — is on a first-come, first-served basis.

Seat selection fees form a major ancillary, or non-ticket, revenue stream for airlines, and mandating more than half the seats to be offered free of charge could impact their revenue. Over the years, Indian airlines, like global carriers, have been increasingly unbundling services to generate more ancillary revenue through add-ons like preferred seat selection, pre-booked meal services, and on-board food and beverage retail, while keeping base fares low.

How Indian airlines will implement these directives is not clear yet. Theoretically, more free seats could lead to higher selection charges for seats that will still remain chargeable, or even a slight increase in base fares, although such moves would also depend on competition and market factors. As for getting those on the same PNR to sit together, pre-booked seats by other passengers could be a hindrance, and how airlines implement this directive in such cases remains to be seen.

A couple of years ago, the DGCA had asked airlines to ensure that children up to 12 years of age must be seated next to at least one of their parents or guardians travelling on the same PNR without having to pay extra for the seat selection.

Apart from the directives on seat selection, the regulator also asked airlines to facilitate carriage of sports equipment and musical instruments in a "transparent and passenger-friendly manner" subject to safety and operational regulations.

Additionally, airlines have also been asked to bring out clear, transparent policies for carriage of pets.

A couple of major Indian carriers allow pets on board, subject to cage and weight specifications, while few others allow carriage of pets only in the cargo hold of the aircraft.

The DGCA has also instructed airlines to ensure strict adherence to passenger rights framework, particularly in cases of delays, cancellations and denial of boarding; prominently display of passenger rights across airline websites, mobile applications, booking platforms, and airport counters; and to have clear communication of passenger entitlements in regional languages to ensure wider accessibility and awareness.

The Ministry of Civil Aviation said it "remains committed to enhancing passenger experience, ensuring transparency, reducing grievances and upholding the highest standards of safety across the aviation ecosystem".

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

JANSATTA DELHI 19 MARCH 2026

'उड़ानों में 60% सीट पर अतिरिक्त शुल्क न लें'

नई दिल्ली, 18 मार्च (ब्यूरो)।

सरकार ने विमानन कंपनियों से बुधवार को कहा कि घरेलू उड़ानों में 60 फीसद सीट पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क न लेने को कहा गया है।

इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय के प्रयासों के तहत यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए विमानन कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि एक ही पीएनआर (पैसेंजर नेम रिकार्ड) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को उड़ान में साथ बैठाया जाए। इन कदमों की घोषणा करते हुए मंत्रालय ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि हर उड़ान में कम से कम 60 फीसद सीट बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं ताकि निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित हो सके।

एक विमानन कंपनी के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में केवल 20 फीसद सीट बिना शुल्क के बुक की जा सकती हैं जबकि बाकी सीट के लिए भुगतान करना पड़ता है। मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ बैठाया जाए या आस-पास की सीट दें।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

LOKSATYA DELHI 19 MARCH 2026

फ्लाइट में एक ही PNR पर साथ-साथ मिलेगी सीट

नई दिल्ली,एजेंसी। एक ही पीएनआर पर बुक कराये गये टिकट पर अब यात्रियों को फ्लाइट में एक साथ सीट देना अनिवार्य कर दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी विमान सेवा कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कम से कम 60 प्रतिशत सीटों का आवंटन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के करना अनिवार्य होगा। साथ ही एक ही पीएनआर पर बुक कराये गये टिकट के लिए यात्रियों को एक साथ सीट देनी होगी, जहां तक संभव हो उन्हें अगल-बगल की सीट प्रदान करने के लिए कहा गया है। आमतौर पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आयी हैं जिनमें एक ही परिवार के लोगों को एक ही पीएनआर पर बुक कराये गये टिकट पर काफी दूर-दूर बैठने के लिए सीट आवंटित की जाती थी जिससे लोगों को परेशानी होती थी।

एयरलाइंस एक साथ पसंदीदा सीट के चयन पर मोटा शुल्क वसूलती थीं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि उसने डीजीसीए के माध्यम से यह निर्देश जारी किया है ताकि यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके। यह यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के उसके सतत प्रयासों का एक हिस्सा है। निर्देश में कहा गया है कि सुरक्षा और परिचालन संबंधी नियमों का ध्यान रखते हुए खेल उपकरणों और वाद्य यंत्रों को फ्लाइट में ले जाने के लिए पारदर्शी और यात्री-अनुकूल व्यवस्था की जानी चाहिये। एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे पालतू जानवरों को फ्लाइट में ले जाने के बारे में भी स्पष्ट और पारदर्शी नीति तैयार करें। डीजीसीए ने विमान सेवा कंपनियों से यात्रियों के अधिकार संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है, विशेषकर उन मामलों में जहां फ्लाइट में देरी हुई हो या फ्लाइट रद्द हुई हो या फिर यात्री को कंफर्म टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से मना किया गया हो। विमान सेवा कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप, अन्य बुकिंग प्लेटफॉर्म और हवाई अड्डों पर मौजूद उनके काउंटरों पर यात्रियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। निर्देश दिया गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी यात्रियों के अधिकारों की उन्हें जानकारी प्राप्त जानकारी दी जाये।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

MINT DELHI 19 MARCH 2026

SpiceJet has four weeks to deposit ₹145 cr in Maran dispute

Krishna Yadav
krishna.yadav@livemint.com
NEW DELHI

The Delhi High Court on Wednesday granted budget airline SpiceJet a final opportunity to deposit ₹144.5 crore within four weeks in its ongoing arbitration dispute with Kalanithi Maran and KAL Airways Pvt. Ltd.

The order piles compliance pressure on the firm after multiple rounds of litigation, with courts rejecting its plea that it faces liquidity constraints and warning that a cash payout will hamper operations. Justice Subramonium Prasad rejected SpiceJet's plea seeking modification of the January order, under which the airline had proposed furnishing an immovable property worth about ₹148 crore as security instead of making the cash deposit.

The judge indicated that the plea could have been rejected outright but was heard at length given broader stakeholder concerns.

"Dismissed. I am extending the time by four more weeks to deposit the money. Sell the property in four weeks," Justice Prasad said.

The court declined to allow the use of property as security, despite the airline's submission that depositing the amount would create operational challenges.

The plea by Spicejet to offer property as security instead a cash deposit was rejected. MINT

Appearing for SpiceJet, senior counsel Amit Sibal argued that the immediate payment would disrupt operations of the airline.

"Can I just point out that my operations will be affected? There are 22,000 passengers and 7,000 employees. Nearly 40% of my flights go to the Gulf, which have been cancelled. That is causing a further liquidity problem. Therefore, I am offering an unencumbered property—I have furnished a letter," Sibal told the court.

HC grants airline final four-week extension to deposit ₹144.5 cr in its dispute with Kalanithi Maran and KAL Airways

SpiceJet argued that it is facing a liquidity crunch due to flight cancellations on Gulf routes. "It is only because of the problems that will be faced by the staff and the people working there that I have heard this matter for so long," Justice Prasad said.

The application was filed on 6 March after the Supreme Court of India, on 27 February, refused to stay the High Court's earlier order directing the airline and its promoter Ajay Singh to deposit ₹144.51 crore.

The SC also imposed costs of ₹1 lakh on the airline for prolonging the litigation.

The refusal meant SpiceJet was required to comply with the High Court's 19 January order within six weeks, prompting the airline to move a fresh plea seeking permission to furnish property instead of cash. In its 19 January order, the High Court recorded that SpiceJet had admitted ₹194.51 crore was due and payable under earlier Supreme Court directions.

For an extended version of this story, go to livemint.com.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

MINT DELHI 19 MARCH 2026

Airlines barred from extra fee on 60% domestic seats

Currently, only 20% of airline seats do not carry an extra charge of ₹200-2,100

PTI
feedback@livemint.com
NEW DELHI

The government on Wednesday said airlines have been asked not to levy any additional charge for 60% of seats in domestic flights. Airlines have also been asked to ensure that those travelling on the same passenger name record (PNR) are seated together.

Announcing the steps on Wednesday, the civil aviation ministry said the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has asked airlines to make sure at least 60% seats are allocated free of charge to ensure fair access.

At present, 20% of the seats can be booked free of charge while the rest are paid for, according to an airline official. Generally, airlines charge ₹200-2,100 for choosing seats, depending on various factors, including front rows and extra leg room, a travel industry executive said.

"Passengers travelling on the same PNR are to be seated together, preferably in adjacent seats," the ministry said in a release. These directions are applicable for domestic flights, an official said.

According to the release, carriage of sports equipment and musical instruments is to be facilitated in a transparent and passenger-friendly manner, subject to applicable safety and operational regulations.

Moreover, airlines have been asked to bring transparent policies for "carriage of pets".

BLOOMBERG

The ministry also emphasized that there should be strict adherence to the passenger rights framework, particularly in cases of delays, cancellations and boarding denial.

There should be a prominent display of passenger rights across airline websites, mobile apps, booking platforms, and airport counters, as well as clear communication of passenger entitlements in regional languages to ensure wider accessibility and awareness, it added.

The ministry said India has emerged as the third-largest domestic aviation market globally, with air travel becoming increasingly accessible and inclusive under the regional air connectivity scheme Udan. Indian airports handle over 500,000 passengers daily, reflecting the rapid growth of the sector, it noted.

Specific details related to the directives, such as the date from which the new norms will be applicable, were not available.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

MILLENNIUM POST DELHI 19 MARCH 2026

Govt directs airlines to offer 60% seats free, ensure families sit together

OUR CORRESPONDENT

These directives apply to domestic routes and come amid growing complaints over airlines charging high fees for services such as seat selection

NEW DELHI: The civil aviation authorities have directed airlines to make a majority of seats on domestic flights available without extra charges as part of new measures aimed at improving passenger convenience.

In an announcement on Wednesday, the Ministry of Civil Aviation said the Directorate General of Civil Aviation has instructed carriers to allocate at least 60 per cent of seats free of cost. Currently, only around 20 per cent of seats can be selected without paying additional fees, according to an airline official.

The ministry also stated that passengers booked under the same PNR should be seated together, "preferably in adjacent seats", to ensure families and groups can travel comfortably.

These directives apply to domestic routes and come amid growing complaints over airlines charging high fees for services such as seat selection.

Civil Aviation Minister K Rammohan Naidu said in a post on X that the government has issued key directions to strengthen Continued on P4

Govt directs

passenger facilitation. "60 per cent seats free of charge, assured seating together for families, and clear, transparent norms for carriage of sports equipment, musical instruments and pets," he said.

He added that enforcement of passenger rights will be strengthened, with greater clarity during flight delays and cancellations, as authorities seek to improve transparency and accountability across the sector.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

MILLENNIUM POST KOLKATA 18 MARCH 2026

Air India to operate 36 addtional flights to Europe, Canada during March 19-28

NEW DELHI: Air India will operate 36 additional flights to destinations in Europe and North America between March 19 and 28 amid the West Asia conflict impacting travel plans of people.

In a statement on Tuesday, the airline said it would operate additional services on Delhi-London (Heathrow), Mumbai-London (Heathrow), Delhi-Frankfurt, Delhi-Zurich & Delhi-Toronto routes.

"These flights will add 10,012 seats on the five routes, further boosting capacity and providing more choice to travellers when travel options remain limited," it said.

The West Asia conflict involving the US, Israel and Iran that started on February 28 has disrupted flight operations, and airlines have curtailed their services in the region. MPOST

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE MORNING STANDARD DELHI 19 MARCH 2026

No extra fee for 60% of seats on domestic routes for fliers

S LALITHA @ New Delhi

AMID complaints about airlines levying high additional charges for allocating seats on flights, the Union civil aviation ministry on Wednesday directed that a minimum of 60% of seats on all domestic flights be allocated free of charge.

In another passenger-friendly measure, the ministry asked airlines to ensure that passengers traveling on the same PNR (Passenger Name Record) are seated together.

"Passengers travelling on the same PNR are to be seated together, preferably in adjacent seats," the ministry said in a release.

The airlines were also directed to bring out clear, transparent policies for carrying pets on board. Besides, they must ensure that carriage of sports equipment and musical instruments on board are facilitated in a transparent and passenger-friendly manner without compromising on applicable safety and operational regulations.

Additionally, all airlines must strictly adhere to the passenger rights framework, particularly in cases of delays, cancellations, and denial of boarding. The rights of passengers must be prominently displayed across the airline's websites, mobile applications, booking platforms, and airport counters, the ministry said.

"60 per cent seats free of charge, assured seating together for families, and clear, transparent norms for carriage of sports equipment, musical instruments & pets," Civil Aviation Minister K Rammohan Naidu said in a post on X.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

NAVBHARAT TIMES DELHI 19 MARCH 2026

'घरेलू एयरलाइंस 60% सीटों की बुकिंग पर न लें अतिरिक्त शुल्क'

नागर विमानन मंत्रालय के निर्देश, एक PNR पर टिकट बुक तो नजदीक सीटें दें

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

नागर विमानन मंत्रालय ने तमाम भारतीय एयरलाइंस से कहा है कि वह डोमेस्टिक फ्लाइटों की बुकिंग में 60 फीसदी सीटों पर यात्रियों से बुकिंग करते वक्त किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लें। हवाई जहाज की 60 फीसदी सीटों की बुकिंग उनके ऑरिजनल फेयर पर बुक करें।

मंत्रालय ने एयरलाइंस को यह निर्देश डीजीसीए के माध्यम से दिए हैं। एयरलाइंस को यह भी कहा गया है कि वह एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले एक से अधिक यात्रियों को एक साथ या आसपास ही सीट दें। ऐसा नहीं कि सेम पीएनआर पर बुक टिकट में एक यात्री को फ्लाइट के बीच में सीट दे दी तो अन्य को आगे-पीछे सीट बुक कर दी। एक ही पीएनआर पर बुकिंग करते वक्त एयरलाइंस को इस बात का खास ख्याल रखना होगा। अधिकारी ने बताया कि ये निर्देश घरेलू उड़ानों पर लागू होंगे, इंटरनेशनल फ्लाइटों के लिए नहीं।

> अधिकारी ने बताया कि ये निर्देश इंटरनेशनल फ्लाइटों के लिए नहीं है।

अभी कई सर्विस के लिए वसूल रहे एक्स्ट्रा चार्ज

सीट बुकिंग करते वक्त एयरलाइंस विभिन्न सर्विस के लिए यात्रियों से एक्स्ट्रा चार्ज वसूल रही है। ऐसे में मंत्रालय ने एयरलाइंस को निर्देश दिए है कि वह 60 फीसदी बुकिंग पर यात्रियों से किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूलेगी। मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइंस को यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देनी होगी।

पालतू जानवरों के लिए भी बनानी होगी स्पष्ट नीति

पालतू जानवरों को ले जाने के मामले में भी एयरलाइंस को पारदर्शी और स्पष्ट नीति बनानी होगी। फ्लाइट के तय समय से अधिक समय तक डिले होने और कैंसल होने की स्थिति में यात्रियों को पैसा वापस करने के मामलों में पैसेंजर फ्रेंडली नियम होने चाहिए। यात्रियों की शिकायतों का निवारण उनकी भाषा में किया जाए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE PIONEER DELHI 19 MARCH 2026

Ensure 60% seats free, airlines told

RAJESH KUMAR ■ New Delhi

The Ministry of Civil Aviation on Wednesday directed airlines to ensure that at least 60 per cent of seats on every flight are provided free of charge. The move follows widespread complaints over additional charges for seat selection, particularly for window, aisle and extra-legroom seats. Currently, only a limited number of seats — often middle seats at the back — are available without extra cost. The new directive is expected to reduce the financial burden on passengers, for whom seat selection has increasingly become an additional expense rather than an add-on.

Civil Aviation Minister K Rammohan Naidu said the Government has issued "important directions to further strengthen passenger facilitation measures."

Representative image iSTOCK

"60 per cent seats free of charge, assured seating together for families, and clear, transparent norms for carriage of sports equipment, musical instruments & pets," he posted on X.

CONTINUED ON >> P4

Ensure 60% seats free, airlines told

The Government has also reiterated that passengers booked under the same PNR should be seated together, preferably in adjacent seats — a long-standing concern for families and group travellers. In April 2024, the Directorate of Civil Aviation (DGCA) had already mandated that young children must be seated with at least one parent or guardian without additional charges.

To address complaints over damaged belongings, airlines have been directed to handle sports equipment and musical instruments in a "transparent and passenger-friendly manner," subject to safety norms. The ministry further stressed strict compliance with passenger rights in cases of delays, cancellations and denied boarding. Airlines must prominently display these rights across websites, mobile apps, booking platforms and airport counters, and communicate them clearly, including in regional languages.

The ministry said passenger facilitation remains a top priority, alongside initiatives such as UDAN Cafes for affordable food, Flybrary for free books and free Wi-Fi at airports.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE STATESMAN DELHI 19 MARCH 2026

Government mandates free seat selection for 60 per cent seats on flights

STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 18 March

In a broader push to improve passenger convenience and standardise airline policies, the Ministry of Civil Aviation has directed airlines to offer free seat selection for at least 60 per cent of seats on every flight.

The new direction was issued through the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) and aims to ensure fair access for passengers and improve transparency in airline practices.

Further, the directions also said that the passengers travelling on the same PNR to be seated together, preferably in adjacent seats.

DGCA also instructed the airlines to maintain strict adherence to passenger rights framework, particularly in cases of delays, cancellations and denied boarding.

In terms of baggage policy, the DGCA asked the airlines to ensure the carriage of sports equipment and musical instruments to be facilitated in a transparent and passenger-friendly manner, subject to applicable safety and operational regulations.

Airlines shall also bring out clear, transparent policies for carriage of pets, it said.

In order to maintain transparency, the DGCA has asked the airlines to maintain prominent display of passenger rights across airline websites, mobile applications, booking platforms, and airport counters.

Clear communication of passenger entitlements in regional languages to ensure wider accessibility and awareness, it said.

India has emerged as the third-largest domestic aviation market globally, with air travel becoming increasingly accessible and inclusive under the UDAN scheme. Indian airports today handle over five lakh passengers daily, reflecting the rapid growth of the sector, as per the information shared by the Ministry of Civil Aviation.

It further said passenger facilitation remains the highest priority of the Ministry of Civil Aviation.

In line with this commitment, the Ministry has undertaken several passenger-centric initiatives to enhance ease of travel, including UDAN Yatri Cafés for affordable food, Flybrary for free access to books and provision of free Wi-Fi at airports.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

THE TRIBUNE DELHI 19 MARCH 2026

Don't levy selection charges on 60% seats: Govt to airlines

UJWAL JALALI
TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, MARCH 18

The Ministry of Civil Aviation has directed the airlines not to levy additional charges for 60 per cent of seats in domestic flights on passengers. It also asked them to ensure that passengers travelling on the same PNR were seated together.

Passengers with same PNR can now sit together

The directions, issued through the Directorate General of Civil Aviation (DGCA),

CONTINUED ON PAGE 8

Don't levy selection charges...

seek to bring greater transparency and uniformity in airline practices while addressing long-standing passenger grievances over paid seat selection and scattered allotments. Under the new norms, the airlines will be required to assign adjacent seats, as far as possible, to passengers booked under a single PNR, ensuring that families are not split across rows — a common complaint in recent years.

The ministry said the measures were part of a broader push to strengthen passenger facilitation in India's fast-growing aviation sector, which now handles over five lakh passengers daily and ranks as the world's third-largest domestic market.

The DGCA has also asked the airlines to adopt transparent and passenger-friendly policies for carriage of sports equipment, musical instruments and pets, within safety and operational guidelines.

Reinforcing passenger rights, the regulator has mandated strict adherence to norms in cases of delays, cancellations and denied boarding. The airlines will also have to prominently display passenger rights on their websites, mobile applications, booking platforms and airport counters, and communicate entitlements in regional languages.

The ministry said the steps built on ongoing initiatives such as affordable airport eateries under UDAN Yatri Cafés, free Wi-Fi and access to books through "Flybrary".